घटती घटना

सत्य के साथ...जनहित में बात...

www.ghatatighatana.com अम्बिकापुर,वर्ष 22, अंक - 318- रविवार 20- सितम्बर 2026,पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रूपये RNI Reg.No.- CHHHIN/2004/15050,डाक पंजीयन. क्रं. 13/Surguja DN/ 2026-2028

प्रधानमंत्री मोदी ने 20वें रोजगार मेले में 51 हजार से ज्यादा नियुक्ति पत्र बांटे....

देश विकसित भारत के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है इसमें आप जैसे युवाओं की बड़ी भूमिका : पीएम मोदी

नई दिल्ली,19 सितम्बर 2026। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को 20वें रोजगार मेले में 51 हजार से ज्यादा नियुक्ति पत्र बांटे। मोदी ने नए चुने कर्मचारियों को वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी ऐसे समय में भारत सरकार से जुड़े हैं, जब देश बहुत बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है। ये लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाने का। इसमें आप जैसे युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। सरकार में रहते हुए आपको हर वो निर्णय लेना है, जो विकसित और आत्मनिर्भर भारत के अभियान को निरंतर सशक्त करे। भारत के युवाओं के सामर्थ्य की एक और तस्वीर हमारे स्टार्टअप इको सिस्टम में दिखाई देती है। भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इको सिस्टम है। और भारत की स्टार्टअप स्टोरी अब केवल बड़े शहरों की कहानी नहीं है। आज करीब आधे रिकग्नाइज्ड स्टार्टअप टियर2 और टियर3 शहरों में हैं। कुछ ही दिन पहले ब्रिक्स समिट खत्म हुआ है। भारत ने यह सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि ब्रिक्स का सहयोग सिर्फ सरकारों तक ही सीमित न रहे; बल्कि हमारे एंटरप्रेन्योर्स,किसान, महिलाएं और युवा भी इस साझेदारी में सक्रिय रूप से शामिल हों। इसी सोच के साथ'ब्रिक्स कनेक्ट'और 'ब्रिक्स एमएसएमई कोऑपरेशन पोर्टल' जैसी पहल शुरू की गई हैं।

पिछले कुछ सालों में भारत सरकार का लगातार ध्यान युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करने पर रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति,स्किल इंडिया मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना या अप्रेंटिसशिप को बढ़ावा देने के प्रयास- हमारी कोशिश यही रही है कि युवाओं की शिक्षा और उनके कौशल को बदलती अर्थव्यवस्था की जरूरतों के अनुरूप बनाया जाए। प्रधानमंत्री ने 22 अक्टूबर 2022 को रोजगार मेले का पहला फेज शुरू किया था। तब पीएम ने कहा था...हमारा लक्ष्य देश के युवाओं को 2023 के आखिर तक 10 लाख सरकारी नौकरियां देना था। लोकसभा चुनाव से पहले 12 फरवरी 2024 को 12वां रोजगार मेला आयोजित हुआ था, जिसमें सबसे ज्यादा 1 लाख जॉब लेटर बांटे गए थे।

रोजगार मेला देश के 45 स्थानों पर...

आज जिन युवाओं को नियुक्ति पत्र मिले हैं उनकी नियुक्तियां केंद्र सरकार के अलग-अलग विभागों और संगठनों में हुई हैं। रोजगार मेला देश के 45 स्थानों पर आयोजित किया गया। नियुक्ति पत्र पाने वाले अभ्यर्थी केंद्र सरकार के अलग-अलग मंत्रालयों और विभागों में काम शुरू करेंगे। इनमें राजस्व विभाग, रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग और रक्षा मंत्रालय शामिल हैं। अब तक अलग-अलग विभागों और सरकारी संगठनों में करीब 12.75 लाख युवाओं को नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं।

आप जिस मुकाम पर पहुंचे हैं,उसके पीछे आपकी मेहनत

पीएम मोदी ने कहा...देश में त्योहारों का समय शुरू हो चुका है। इन खुशियों के बीच आज का दिन हजारों परिवारों के जीवन में नई खुशी लेकर आया है। आज देश के 51 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी सेवा के लिए नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। आज आप जिस मुकाम पर पहुंचे हैं, उसके पीछे आपकी मेहनत तो है ही। साथ ही आपके माता-पिता और आपके परिजन की भी तपस्या है। मैं आप सभी युवा साथियों को और आपके परिवारजनों को बहुत-बहुत बधाई देता हूं। युवा होने के नाते विशेष तौर पर अन्य युवाओं के प्रति आपकी विशेष जिम्मेदारी है।

भारत जी 20 का इकलौता देश जिसने पेरिस कॉप-21 के 3 कमिटमेंट समय से पूरे किए : प्रधानमंत्री मोदी

नई दिल्ली,19 सितम्बर 2026। पीएम नरेंद्र मोदी ने शनिवार को 'द फ्यूचर ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट डायनेमिक्स' इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में शनिवार को हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का मोबाइल ऐप लॉन्च किया। उन्होंने कहा, भारत जी20 में इकलौता ऐसा देश है,जिसने पेरिस में कॉप-21 समिट में जो भी कमिटमेंट किए थे,उन्हें समय से पूरा करके दिखाया है। कार्बन उत्सर्जन की जिम्मेदारी अक्सर विकासशील देशों पर डाल दी जाती है। जबकि भारत का प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन आज भी दुनिया के औसत से आधे से कम है। दरअसल, पेरिस में 2015 में हुए कॉप-21 सम्मेलन में भारत ने पर्यावरण को लेकर तीन बड़े लक्ष्य तय किए थे। पहला, 2030 तक 2005 के मुकाबले कार्बन उत्सर्जन की तीव्रता 33-35% कम करना था। दूसरा, 2030 तक देश की बिजली क्षमता का करीब 40% हिस्सा गैर-जीवाश्म ऊर्जा से तैयार करना था। तीसरा,पेड़ और जंगल बढ़ाकर 2.5-3 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड सोखने की क्षमता तैयार करना था। हम दुनिया को साथ लेकर पर्यावरण की सुरक्षा के लिए नए तरीके अपना रहे हैं। भारत अपनी पुरानी पर्यावरण संरक्षण की सोच को आधुनिक तरीके से आगे बढ़ा रहा है। 12 साल पहले भारत की सोलर एनर्जी करीब 2 गीगावाट थी, आज यह 160 गीगावाट से ज्यादा हो चुकी है। वहीं, 12 साल में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की संख्या 950 गुना बढ़ी है। विकसित देशों में प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन भारत से करीब 6 गुना ज्यादा है। भारत ने इस बात को वैश्विक मंचों पर लगातार उठाया है।

रेलवे ने आधुनिक सिग्नलिंग से जुड़ी 461 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी

नई दिल्ली,19 सितम्बर 2026। भारतीय रेलवे ने रेल सुरक्षा और परिचालन क्षमता मजबूत करने के लिए उत्तर पूर्व रेलवे के लखनऊ मंडल में 607.7 रूट किलोमीटर पर 'कवच 4.0' लगाने और मध्य रेलवे के सोलापुर मंडल के सात स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की व्यवस्था करने की परियोजनाओं को मंजूरी दी है। दोनों परियोजनाओं की कुल लागत 461 करोड़ रुपये है। रेल मंत्रालय के अनुसार, रेलवे ने लखनऊ मंडल के चिन्हित शेष खंडों में 607.7 रूट किलोमीटर पर कवच 4.0 उपलब्ध कराने के लिए 252 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। इससे मंडल के इन खंडों पर ट्रेनों की सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत होगी। कवच देश में विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है,जिसे रेल परिचालन में सुरक्षा बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। यह सिग्नल पार करने की स्थिति में चालक को सतर्क करने तथा आवश्यकता पड़ने पर स्वतः ब्रेक लगाने में मदद करता है और ट्रेन की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए परिचालन पर निगरानी रखता है। रेलवे ने इसके अलावा मध्य रेलवे के सोलापुर मंडल के सात स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग लगाने के लिए 209 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। ये स्टेशन मोहोल, मुंधेवाड़ी, बाले, सोलापुर, होटगी जंक्शन-होटगी ए केबिन, शाहाबाद और वाडी जंक्शन हैं। ये सभी स्टेशन हाई डेंसिटी नेटवर्क (एचडीएन)-7 मार्ग पर हैं, जहां कवच, स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग (एबीएस) और केंद्रीकृत यातायात नियंत्रण (सीटीसी) से जुड़े कार्यों को भी मंजूरी दी गई है। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग कंप्यूटर आधारित आधुनिक सिग्नलिंग प्रणाली है, जो पारंपरिक रिले आधारित इंटरलॉकिंग की जगह लेती है।

इससे प्वाइंट और सिग्नल का अधिक विश्वसनीय नियंत्रण, खराबी का तेजी से पता लगाने और उसे दूर करने तथा रखरखाव को सुगम बनाने में मदद मिलती है। मंत्रालय के अनुसार, दोनों परियोजनाएं रेल नेटवर्क में स्वदेशी कवच प्रणाली के विस्तार, सिग्नलिंग ढांचे के आधुनिकीकरण और उच्च घनत्व वाले रेल मार्गों पर परिचालन की सुरक्षा एवं दक्षता बढ़ाने के प्रयासों का हिस्सा हैं।

डूसू चुनाव परिणाम : एबीवीपी का 3-1 से दबदबा,निर्दलीय के खाते में उपाध्यक्ष पद

नई दिल्ली,19 सितम्बर 2026। डूसू चुनाव के परिणाम सामने आ चुके हैं। कुल चार प्रमुख पदों में से तीन पर एबीवीपी ने जीत दर्ज की है, जबकि एक पद निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में गया है। वहीं, एनएसयूआई को सभी चार सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। शुरुआती रुझानों से ही मुकाबले में कांटे की टक्कर देखने को मिली और अंत तक जीत-हार का आंकड़ा ऊपर-नीचे होता रहा। अध्यक्ष पद पर एबीवीपी के यश डबास, उपाध्यक्ष पद पर निर्दलीय दीपांशु शौकीन, सचिव पद पर एबीवीपी की रिया छावड़ी और संयुक्त सचिव पद पर एबीवीपी के लक्ष्य राज सिंह ने जीत दर्ज की है। इस तरह एबीवीपी ने तीन पदों पर जीत हासिल की, जबकि एक पद निर्दलीय उम्मीदवार के नाम रहा।

अध्यक्ष पद पर जीते के बाद यश डबास की प्रतिक्रिया

अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज करने के बाद यश डबास ने कहा,यह जीत राष्ट्रभक्ति और संघ की सामूहिक शक्ति की जीत है। पीयू से लेकर डीयू तक के संस्थानों के छात्रों ने हमारी जीत सुनिश्चित करने के लिए काम किया है। कैंपस से एनएसयूआई का पूरी तरह से सफाया हो गया है। एनएसयूआई 4-0 से हार गई है।'उन्होंने कहा,'हमारी मुख्य चिंता यह सुनिश्चित करना होगी कि हर पीजी और हॉस्टल का सुरक्षा ऑडिट कराया जाए। हम सबने सत्या निकेतन में हुई दुर्घटना को देखा है। हम नहीं चाहते कि ऐसी घटना भविष्य में किसी के साथ भी हो और यही हमारी पहली प्राथमिकता होगी। हर कॉलेज,हॉस्टल और पीजी का सुरक्षा ऑडिट कराना। विद्यार्थी परिषद ने पिछली बार 3-1 से जीत हासिल की थी और इस बार भी 3-1 से ही जीती है। अगली बार हम 4-0 से जीतेंगे।'

एबीवीपी की जीत पर नितिन नबीन और जेपी नड्डा ने दी बधाई

डूसू चुनाव परिणाम के बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन और केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने बधाई दी है। नितिन नबीन ने कहा, 'दिल्ली विश्वविद्यालय के मेरे सभी युवा साथियों को डूसू चुनाव में एबीवीपी की ऐतिहासिक जीत पर हार्दिक बधाई। यह जीत सकारात्मक और रचनात्मक छात्र राजनीति में युवाओं के निरंतर विश्वास को दर्शाती है, जो 'राष्ट्र प्रथम'की भावना पर आधारित है। साथ ही,यह 'विकसित भारत' के विजन में योगदान देने के उनके मजबूत संकल्प को भी दर्शाती है।'वहीं,जगत प्रकाश नड्डा ने बधाई देते हुए कहा,'दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव 2026 में अध्यक्ष, सचिव व संयुक्त सचिव पद पर शानदार जीत हासिल करने पर एबीवीपी के सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देता हूं।'

जीते हुए प्रत्याशियों को मिले कुल मत

- अध्यक्ष पद पर एबीवीपी के यश डबास- 24,576
- उपाध्यक्ष पद पर निर्दलीय दीपांशु शोकीन-30,615
- सचिव पद पर एबीवीपी की रिया छावड़ी-21,650
- संयुक्त सचिव पद पर एबीवीपी के लक्ष्य राज सिंह- 16,615

मध्य प्रदेश में उफनते नाले में बही कार,8 की मौत..

आगर मालवा,19 सितम्बर 2026। मध्य प्रदेश के आगर-मालवा के नलखेड़ा में मां बगलामुखी मंदिर के पास बरसाती नाले में कार बहने से 8 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 3 बच्चे शामिल हैं। 7 मृतक ओडिशा के हैं, जबकि कार ड्राइवर अरुण गोयल आगर-मालवा के बड़ौद का रहने वाला था। सभी श्रद्धालु मां बगलामुखी मंदिर में दर्शन के लिए आए थे। उन्होंने उज्जैन से कार किराए पर ली थी। एसपी दिलीप कुमार सोनी के मुताबिक, हादसा रात करीब 3 बजे हुआ। शुरुआती जांच में मौत का कारण डूबना सामने आया है। पुलिस मंदिर और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। ड्राइवर समेत 6 मृतकों की पहचान हो गई है। ड्राइवर अरुण गोयल के अलावा मृतकों में राधा रानी बहेरा,ज्ञानेंद्र कुमार बहेरा,रितारानी पत्नी ज्ञानेंद्र बहेरा,कृष्णा राजवीर पुत्र शिवप्रसाद बहेरा और शिवप्रसाद बहेरा शामिल हैं।

मोदी ने आगर मालवा हादसे पर दुःख जताया

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले में बारिश से उफनाए नाले में कार बह जाने से हुई आठ लोगों की मौत पर शनिवार को दुख जताया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से दो-दो लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक्स पोस्ट में कहा,आगर मालवा,मध्य प्रदेश में हुआ हादसा अत्यंत पीड़ादायक है। मैं अपने प्रियजनों को खोने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। मोदी ने कहा कि हादसे में जान गंवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के निकटतम परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से दो लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। उन्होंने कहा कि घायलों को 50 हजार रुपये दिए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि आगर मालवा जिले के नलखेड़ा में मां बगलामुखी मंदिर के पास भारी बारिश के कारण नाला उफान पर आ गया था। इसी दौरान उज्जैन से आए ओडिशा के श्रद्धालुओं को ले जा रही कार पानी के तेज बहाव में बह गई। हादसे में तीन बच्चों सहित आठ लोगों की मौत हो गई। बताया गया है कि क्षेत्र में रातभर हुई भारी बारिश के बाद नाले का जलस्तर बढ़ गया था, जिसके कारण यह हादसा हुआ।

इंदौर में 'छात्रों की गूंज'....सिस्टम अंधभक्त पैदा करता है,वह नहीं चाहता कि छात्र सवाल पूछें : राहुल गांधी

इंदौर,19 सितम्बर 2026। राहुल गांधी ने इंदौर में 'छात्रों की गूंज' को संबोधित किया। कार्यक्रम के लिए 20 से 25 हजार युवा पहुंचे। छात्रों से सवाल-जवाब के दौरान राहुल ने कहा...सिस्टम नहीं चाहता कि स्टूडेंट्स सवाल पूछें, इसलिए वह अंधभक्त पैदा करता है। उन्होंने कहा...छात्रों का सिस्टम से भरोसा उठ गया है, हालांकि कुछ जगह कैंडिडेट्स की भी गलती है। इस पर सामने बैठे छात्रों ने जवाब दिया...सर, हम सिस्टम से हार गए। कांग्रेस ने बताया कि कार्यक्रम के लिए करीब 2 लाख रजिस्ट्रेशन हुए। इसकी अनुमति 31 शर्तों के साथ मिली।

पूरी व्यवस्था को रिवाइंड किया जा रहा है : राहुल गांधी ने कहा कि पहले देश में आईआईटी और स्कूल बनाए गए, लेकिन अब पूरी व्यवस्था को रिवाइंड किया जा रहा है। उन्होंने कहा,मैं आपको आंकड़े दिखाऊंगा। सबूत के साथ बताऊंगा कि शिक्षा कैसे बर्बाद हो रही है।' इसके बाद उन्होंने आंकड़ों की स्लाइड दिखाई।

सिस्टम को स्टूडेंट से खतरा,क्योंकि वह सवाल पूछता है...

राहुल गांधी ने कहा कि सिस्टम को स्टूडेंट से खतरा है,क्योंकि स्टूडेंट सवाल पूछता है। उन्होंने कहा कि छात्र सवाल करता है कि अमित शाह के बेटे क्रिकेट एसोसिएशन के चेयरमैन कैसे बन गए? वह सवाल करता है कि हिंदुस्तान के पूरे बिजनेस को दो लोगों ने कैसे कैप्चर कर लिया? छात्र यह भी पूछता है कि न्यायपालिका और दूसरी संस्थाएं अपना काम क्यों नहीं करतीं और चुनाव आयोग अपना काम क्यों नहीं करता? राहुल ने कहा...इसीलिए सिस्टम स्टूडेंट नहीं चाहता, सिस्टम अंधभक्त चाहता है।' उन्होंने कहा कि अंधभक्त स्टूडेंट के विपरीत होता है। जहां स्टूडेंट सवाल पूछता है और जिज्ञासु होता है, वहां अंधभक्त अपनी ही दुनिया में रहता है।

स्टूडेंट मोहब्बत की बात करता है,अंधभक्त नफरत फैलाता है...

राहुल गांधी ने कहा कि जहां स्टूडेंट मोहब्बत की बात करता है और प्यार व सम्मान से बात करता है, वहां अंधभक्त नफरत फैलाता है। जहां स्टूडेंट विनम्र होता है और दूसरों की बात सुनता है, वहां अंधभक्त अहंकार से भरा होता है। उन्होंने कहा कि जहां स्टूडेंट डरता नहीं और निडर होता है, वहां अंधभक्त डरपोक होता है। राहुल के मुताबिक,जहां स्टूडेंट महिलाओं का सम्मान करता है,वहां अंधभक्त पितृसतात्मक सोच रखता है और महिलाओं पर हमला व उनका अपमान करता है।

चुनाव आयोग ने बदले आईएसएफ-एजेयूपी के चुनाव चिह्न...नौशाद को 'अलमारी' और हुमायूं को 'टेबल'

कोलकाता,19 सितंबर 2026। तृणमूल कांग्रेस का चुनाव चिह्न 'जोड़ा फूल' फ्रीज होने के बाद, चुनाव आयोग द्वारा प्रतीकों के पुनर्वितरण में भांगड़ के विधायक नौशाद सिद्दीकी और हुमायूं कबीर को नए चुनाव चिह्न आवंटित किए गए हैं। इंडियन सेक्युलर फ्रंट (आईएसएफ) के हाथ से 'लिफाफा' वापस लेकर इसे पहले ही ऋतब्रत बनर्जी की 'डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस' को सौंप दिया गया था। अब नौशाद की पार्टी को 'अलमारी' चुनाव चिह्न दिया गया है। वहीं, हुमायूं कबीर की 'आम जनता उन्नयन पार्टी' (एजेयूपी) से 'बांसुरी' का चिह्न वापस लेकर उन्हें 'टेबल' दिया गया है। आगामी 6 अक्टूबर को राज्य के दो हाई-वोल्टेज विधानसभा क्षेत्रों - नंदीग्राम और रेजीनगर में उपचुनाव होने हैं। मतदान के इस बेहद अहम समय में चुनाव चिह्न बदलने के कारण हुमायूं कबीर गहरी मुश्किल में पड़ गए हैं। साल 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले नई पार्टी बनाकर बांसुरी के चिह्न पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे कबीर को पहले से ही इस बात का अंदेशा था कि उपचुनाव में यह चिह्न उनके पास रहेगा या नहीं। शनिवार को उनकी यह आशंका सच साबित हो गई। चुनाव आयोग ने हुमायूं से 'बांसुरी' छीनकर इसे दक्षिण भारतीय स्टार थलपति विजय की पार्टी 'टीवीके' को आवंटित कर दिया है और हुमायूं को 'टेबल' चुनाव चिह्न दिया गया है। दूसरी तरफ,अपना 'लिफाफा' चिह्न बचाने की लड़ाई में नौशाद सिद्दीकी को भी अंततः हार का सामना करना पड़ा है। इसी साल मार्च में आईएसएफ नेतृत्व ने नियमों के तहत चुनाव आयोग में 'लिफाफा' चिह्न पंजीकृत कराया था।

बंगाल उपचुनाव में रेजीनगर से ममता के प्रत्याशी फिर पलटे

सुबह कहा...नहीं लड़ूंगा,दोपहर में बोले...लड़ूंगा

मुर्शिदाबाद,19 सितम्बर 2026। पश्चिम बंगाल में विधानसभा की 2 सीटों के उपचुनाव के पहले सियासी उथल-पुथल देखने को मिल रही है। रेजीनगर में टीएमसी उम्मीदवार रबीउल आलम चौधरी ने शनिवार सुबह 10 बजे चुनाव से हटने का ऐलान किया, लेकिन करीब 3 घंटे बाद ही दोपहर एक बजे यूटर्न ले लिया। रबीउल ने सुबह हटने का ऐलान करते वक्त पार्टी का पुराना चुनाव चिह्न 'जोड़ा घासफूल' नहीं मिलने और नया चिह्न 'फुटबॉल प्लेयर' मिलने को इसकी वजह बताया था। हालांकि, ममता बनर्जी से बातचीत के बाद रबीउल ने कहा,मैं चुनाव लड़ूंगा। इससे एक दिन पहले नंदीग्राम में भी ममता गुट की उम्मीदवार सॅचिता प्रधान डे ने नामांकन वापस ले लिया था। रेजीनगर और नंदीग्राम सीटों पर 6 अक्टूबर को उपचुनाव होगा और 9 अक्टूबर को मतगणना होगी। नंदीग्राम सीट शुभेंदु अधिकारी के इस्तीफे के बाद और रेजीनगर सीट हुमायूं कबीर के इस्तीफे के बाद खाली हुई है।

संपादकीय

फिर उठा वैवाहिक दुष्कर्म का प्रश्न

हाल में ऋषिकेश साहू बनाम कर्नाटक राज्य एवं अन्य मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने वैवाहिक दुष्कर्म से जुड़े एक ऐसे प्रश्न को सामने रखा,जिसका उत्तर केवल कानून की किसी एक धारा में तलाशना आसान नहीं है। अदालत यह विचार कर रही थी कि जब तक विवाह के भीतर पति द्वारा पत्नी के साथ बनाए यौन संबंध को दुष्कर्म की श्रेणी से बाहर रखने वाले कानूनी अपवाद की संवैधानिक वैधता पर अंतिम निर्णय नहीं हो जाता,तब तक क्या उसी अपवाद के रहते किसी पति के खिलाफ दुष्कर्म के आरोप में अभियोजन चलाया जा सकता है? यहां एक ओर विवाह के भीतर महिला की सहमति, गरिमा और शारीरिक स्वायत्तता का प्रश्न है तो दूसरी ओर किसी व्यक्ति को उस कृत्य के लिए दंडित किए जाने का प्रश्न भी है, जिसे कानून उस समय अपराध के दायरे से बाहर रखता है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई ने इसी टकराव को फिर से हमारे सामने ला दिया है।

वर्ष 2017 में दिल्ली हाई कोर्ट के सामने वैवाहिक दुष्कर्म के अपवाद को चुनौती देने वाली दो याचिकाएं पहुंचीं। इन पर दिए गए फैसले में एक ही पीठ के दो न्यायाधीशों की राय अलग-अलग थी। न्यायमूर्ति राजीव शकधर ने कहा,विवाह में प्रवेश करने वाली महिला अपने पति के अधीन नहीं हो जाती और न ही वह हर परिस्थिति में यौन संबंध के लिए अपनी स्थायी सहमति देती है। दूसरी ओर न्यायमूर्ति सी. हरि शंकर ने वैवाहिक दुष्कर्म को अपराध की श्रेणी में लाने से असहमति जताते हुए कहा,यह अपवाद कहता है कि पति और पत्नी के बीच यौन कृत्य दुष्कर्म नहीं है। न्यायालय की इन दोनों राय के बीच केंद्र सरकार एक अलग दृष्टिकोण रखती है। 2024 में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दाखिल अपने हलफनामे में वैवाहिक दुष्कर्म के अपवाद को हटाने का विरोध किया। सरकार ने माना कि पति को निश्चित रूप से पत्नी की सहमति का उल्लंघन करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है,लेकिन विवाह जैसी संस्था के भीतर होने वाले कृत्य को भारत में मान्य दुष्कर्म के अपराध के रूप में देखना अत्यधिक कठोर और इसलिए असंगत माना जा सकता है।

सरकार ने आगे कहा,विवाह से महिला की सहमति समाप्त नहीं होती और उसकी सहमति के उल्लंघन के परिणाम दंडनीय होने चाहिए। ऐसे मामलों से निपटने के लिए भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं और घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 में पहले से ही ऐसे कानूनी प्रविधान मौजूद हैं। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा-3 के अनुसार महिला के साथ किया गया ऐसा यौन व्यवहार,जो उसकी इच्छा के विरुद्ध हो,उसे अपमानित करे या उसकी गरिमा का उल्लंघन करे,यौन हिंसा के दायरे में आता है। यानी विवाह के भीतर महिला के साथ होने वाली यौन हिंसा के लिए कानून में पहले से स्पष्ट प्रविधान मौजूद हैं। ऐसी स्थिति में महिला को संरक्षण देने के साथ-साथ न्यायालय से विभिन्न प्रकार की राहत पाने का अधिकार भी है।

यह समझना होगा कि जिस कानून को बनाने की बात की जा रही है, उसका भारतीय सामाजिक परिप्रेक्ष्य में गंभीर प्रभाव हो सकता है। वैवाहिक दुष्कर्म का प्रश्न उतना सहज नहीं है,जितना इसे केवल महिलाओं की गरिमा की रक्षा के आधार पर सहज बनाने का प्रयास किया जा रहा है। आखिर बंद दरवाजे के भीतर जो कुछ घटित हुआ,उसकी सत्यता की पुष्टि किस आधार पर होगी? क्या मात्र पत्नी का कथन पति को अपराधी घोषित कर देगा? आखिर पति स्वयं को निर्दोष कैसे सिद्ध करेगा? वैवाहिक दुष्कर्म को सामान्य दुष्कर्म के समान अपराध की श्रेणी में रखने की मांग पर इसलिए केवल भावनात्मक दृष्टि से विचार करना पर्याप्त नहीं होगा। दोनों परिस्थितियों के बीच मौजूद सामाजिक और व्यावहारिक अंतर को भी समझना होगा। महिला के साथ यौन हिंसा किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं हो सकती,लेकिन इसके साथ यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण है कि बंद कमरे में घटित किसी घटना को किस प्रकार परिभाषित किया जाएगा,उसके वास्तविक स्वरूप का निर्धारण किस आधार पर होगा और उसका कानून से समाधान करने के क्या सामाजिक परिणाम होंगे? जब पहले से मौजूद कानून महिला को यौन हिंसा से संरक्षण और न्यायिक राहत देने की व्यवस्था करते हैं,तब एक नए आपराधिक प्रविधान की आवश्यकता और उसके दूरगामी प्रभावों पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।

पारिवारिक विवादों में आरोप-प्रत्यारोप की स्थिति से इन्कार नहीं किया जा सकता। इसलिए महिला की शिकायत को गंभीरता से लेने के साथ यह भी विचार करना होगा कि प्रस्तावित कानून का स्वरूप कहीं ऐसे मामलों में नए विवादों और उसके संभावित दुरुपयोग की गुंजाइश तो पैदा नहीं करेगा। किसी महिला के कथन को केवल उसके महिला होने के कारण स्वतः सत्य नहीं मान लिया जाना चाहिए। सत्य और असत्य का संबंध किसी व्यक्ति के लिंग से नहीं,बल्कि तथ्यों से होता है।

हर सामाजिक समस्या का समाधान कानून के माध्यम से तलाशना उचित नहीं है। आवश्यकता ऐसे सामाजिक ढांचे के निर्माण की है, जहां पुरुषों को महिलाओं की गरिमा, सहमति और यौन स्वायत्तता का सम्मान करना सिखाया जाए, न कि हर समस्या का समाधान उन्हें कठघरे में खड़ा करने में तलाशा जाए।

वकालत को सुरक्षित पेशा ही नहीं,सुरक्षित जीवन भी चाहिए : अधिवक्ता देव प्रसाद जोशी

छत्तीसगढ़ में अधिवक्ता संरक्षण की नई परिकल्पना : सुरक्षा,शुरुआती संघर्ष, बीमारी,वृद्धावस्था और न्यायालयीन कार्यस्थल...पांचों मोर्चों पर एक समग्र व्यवस्था की जरूरत...

किसी न्यायालय में जब कोई अधिवक्ता अपने मुवक्किल की ओर से खड़ा होकर तर्क रखता है,तो सामने दिखाई देता है केवल उसका पेशेवर पक्ष।

देवप्रसाद जोशी
रायपुर,छत्तीसगढ़

उसके पीछे एक ऐसा जीवन भी है जिसमें रोज की तैयारी, लगातार अध्ययन, न्यायालयीन दौड़-भाग,मुवक्किलों की जिम्मेदारी और अनिश्चित आय के बीच पेशे को बनाए रखने की चुनौती शामिल होती है।

इसी वास्तविकता से छत्तीसगढ़ में अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को देखने की जरूरत है।

अधिवक्ता संरक्षण का अर्थ केवल यह नहीं होना चाहिए कि किसी अप्रिय घटना के बाद आरोपी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई हो। संरक्षण की अवधारणा इससे आगे जाती है...अधिवक्ता को निर्भय होकर काम करने का वातावरण मिले,युवा अधिवक्ता शुरुआती वर्षों में पेशा छोड़ने को मजबूर न हो,वरिष्ठ अधिवक्ता वृद्धावस्था में आर्थिक असुरक्षा से न जूझे, बीमारी में उपचार के साथ परिवार की चिंता भी कम हो और न्यायालय स्वयं अधिवक्ता के लिए सम्मानजनक कार्यस्थल उपलब्ध कराए।

इसी व्यापक सोच के आधार पर छत्तीसगढ़ में अधिवक्ताओं के लिए एक विशेष संरक्षण एवं कल्याण कानून की आवश्यकता पर विचार किया जाना चाहिए।

अधिवक्ता देव प्रसाद जोशी,छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर एवं सेशन कोर्ट,रायपुर के अनुसार अधिवक्ता संरक्षण की चर्चा को केवल सुरक्षा तक सीमित रखने के बजाय इसे अधिवक्ता के पूरे पेशेवर जीवन-चक्र से जोड़ना अधिक उपयोगी होगा।

पहला सवाल—क्या अधिवक्ता अपने कार्यस्थल पर सुरक्षित है?

अधिवक्ता का चेंबर या कार्यालय उसके पेशे का कार्यस्थल है। वहां मुवक्किल से बातचीत होती है, केस के दस्तावेज देखे जाते हैं और कानूनी रणनीति पर विचार होता है।

यदि कोई व्यक्ति वहां पहुंचकर मारपीट करता है,गाली-गलौज करता है,धमकी देता है या विवाद उत्पन्न कर अधिवक्ता पर दबाव डालने का प्रयास करता है,तो ऐसी घटना को केवल व्यक्तिगत झगड़ा मानकर छोड़ना उचित नहीं होगा।

प्रस्तावित कानून में अधिवक्ता के पेशेवर कार्य में हिंसा, धमकी,जबरदस्ती या गंभीर व्यवधान से संबंधित स्पष्ट प्रावधान होने चाहिए।

गंभीर प्रकृति की घटनाओं में अपराध की परिस्थितियों के अनुरूप गैर-जमानती प्रावधान किए जाने की मांग पर भी विधायी स्तर पर विचार किया जा सकता है। साथ ही कानून में यह सुरक्षा भी होनी चाहिए कि वास्तविक घटना और दुर्भावनापूर्ण या झूठी शिकायत के बीच अंतर करने के लिए उचित कानूनी प्रक्रिया उपलब्ध रहे।

इससे संरक्षण कानून एकतरफा दंड का साधन बनने के बजाय संतुलित कानूनी व्यवस्था के रूप में विकसित हो सकेगा।

दूसरा सवाल—नया अधिवक्ता पेशे में टिके कैसे?

कानून की डिग्री और अधिवक्ता के रूप में पंजीयन के बाद वास्तविक पेशेवर शिक्षा शुरू होती है। पहले कुछ वर्षों में युवा अधिवक्ता को कानून पढ़ने के साथ-साथ यह सीखना पड़ता है कि न्यायालय में आवेदन कैसे प्रस्तुत किया जाता है, केस डायरी कैसे पढ़ी जाती है, साक्ष्य का परीक्षण कैसे किया जाता है, जिरह की तैयारी कैसे होती है और न्यायालयीन प्रक्रिया को व्यावहारिक रूप से कैसे समझा जाता है।

इसी दौरान उसकी आय अक्सर सीमित या अनिश्चित होती है।

इसलिए तीन वर्ष से कम अवधि से पंजीकृत नए अधिवक्ताओं के लिए प्रारंभिक पेशेवर प्रशिक्षण एवं इंटर्नशिप छात्रवृत्ति शुरू करने का प्रस्ताव महत्वपूर्ण हो सकता है।

यह सहायता निर्धारित पात्रता और प्रशिक्षण गतिविधियों से जोड़ी जा सकती है। इसका उद्देश्य मुफ्त आय देना नहीं बल्कि उस शुरुआती अवधि में पेशेवर क्षमता विकसित करने का अवसर देना होना चाहिए, जब अधिवक्ता अपने भविष्य की नींव तैयार करता है।

तीसरा सवाल—65 वर्ष के बाद क्या?

वकालत की खासियत यह है कि इसमें सेवा की कोई सामान्य निर्धारित सेवानिवृत्ति आयु नहीं होती। कई अधिवक्ता लंबे समय तक सक्रिय रहते हैं। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ आय के स्रोत सीमित हो सकते हैं और चिकित्सा खर्च बढ़ सकता है।

इसलिए 65 वर्ष से अधिक आयु के पात्र अधिवक्ताओं के लिए मासिक अधिवक्ता पेंशन अथवा जीवन-निर्वाह सहायता की योजना बनाई जानी चाहिए। पात्रता के लिए न्यूनतम वकालत अवधि, पंजीयन,आय संबंधी मानदंड और अन्य आवश्यक शर्तें निर्धारित की जा सकती हैं। यह योजना अधिवक्ता को केवल आर्थिक सहायता देने की योजना न होकर उस पेशेवर योगदान की सामाजिक स्वीकृति भी हो सकती है जो उसने अपने सक्रिय वर्षों में न्याय व्यवस्था को दिया है।

चौथा सवाल—बीमारी में सिर्फ अस्पताल का बिल नहीं आता किसी अधिवक्ता के गंभीर रूप से बीमार होने पर दो समस्याएं एक साथ पैदा होती हैं। पहली—उपचार का खर्च। दूसरी—काम न कर पाने के कारण आय में कमी।

इसलिए अधिवक्ता कल्याण योजना में कम से कम 20 लाख रुपये तक की कैशलेस स्वास्थ्य उपचार सुविधा

अधिवक्ता तथा उसके पात्र आश्रित परिवार के लिए उपलब्ध कराने की मांग पर विचार किया जाना चाहिए। लेकिन केवल स्वास्थ्य बीमा पर्याप्त नहीं है।

गंभीर बीमारी या चिकित्सकीय रूप से प्रमाणित अस्थायी कार्य-असमर्थता के दौरान पात्र अधिवक्ता को निर्धारित अवधि के लिए जीवन-निर्वाह सहायता भी उपलब्ध कराई जा सकती है।

इस व्यवस्था के लिए मेडिकल प्रमाण, पात्रता और सहायता की अधिकतम अवधि स्पष्ट रूप से तय की जा सकती है।

पांचवां सवाल—क्या न्यायालय अधिवक्ता का भी कार्यस्थल है?

यदि उत्तर हां है,तो फिर न्यायालय परिसर की योजना बनाते समय अधिवक्ता की कार्य संबंधी जरूरतों को भी शामिल करना होगा। कई न्यायालयों में बड़ी संख्या में अधिवक्ता रोज उपस्थित होते हैं। उन्हें बैठने,दस्तावेज देखने, मुवक्किल से चर्चा करने और डिजिटल काम करने के लिए पर्याप्त स्थान की आवश्यकता होती है।

इसलिए प्रत्येक न्यायालय में आवश्यकता के अनुसार :-बार रूम, पर्याप्त सीटिंग, स्वच्छ पेयजल,शौचालय,इंटरनेट,ई-फाइलिंग सुविधा,दस्तावेज स्कैनिंग तथा प्रिंटिंग सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। चेंबर केवल सुविधा नहीं, कानूनी गोपनीयता का स्थान है मुवक्किल और अधिवक्ता के बीच होने वाली बातचीत कई मामलों में अत्यंत संवेदनशील होती है।

यदि किसी व्यक्ति को अपने मुकदमे की जानकारी सार्वजनिक स्थान पर बतानी पड़े तो वह खुलकर अपनी बात रखने में संकोच कर सकता है। इसलिए न्यायालय परिसर में उपलब्ध स्थान के अनुसार अलग चेंबर या प्राइवेट कंसल्टेशन केबिन विकसित किए जाने चाहिए।

चेंबर आवंटन की प्रक्रिया पारदर्शी हो तथा नए और पुराने अधिवक्ताओं के लिए न्यायसंगत व्यवस्था बनाई जाए।

महिला अधिवक्ता और परिवार-अनुकूल न्यायालय परिसर

न्याय व्यवस्था में महिला अधिवक्ताओं की भागीदारी लगातार महत्वपूर्ण हो रही है। इसलिए न्यायालय परिसर की सुविधाओं में उनकी व्यावहारिक जरूरतों को भी शामिल किया जाना चाहिए।स्वच्छ महिला शौचालय,सुरक्षित विश्राम स्थल,मातृत्व संबंधी आवश्यक सुविधाएं तथा आवश्यकता वाले बड़े न्यायालय परिसरों में क्रेच/चाइल्ड-केयर सुविधा विकसित करने पर विचार किया जा सकता है।

यह केवल सुविधा का प्रश्न नहीं बल्कि ऐसा न्यायालयीन वातावरण बनाने का प्रश्न है जिसमें प्रतिभा और पेशेवर क्षमता के सामने अनावश्यक व्यावहारिक बाधाएं कम हों।

अधिवक्ता की मृत्यु का असर परिवार पर पड़ता है

एक अधिवक्ता के निधन के बाद उसके परिवार के सामने आय का संकट उत्पन्न हो सकता है। इसलिए अधिवक्ता कल्याण व्यवस्था में पात्र अधिवक्ता की मृत्यु पर आश्रित परिवार के लिए आर्थिक सहायता,बच्चों की शिक्षा के लिए सहायता तथा उपलब्ध स्वास्थ्य योजना की निरंतरता जैसे प्रावधानों पर विचार किया जाना चाहिए।

डिजिटल युग का अधिवक्ता—सिर्फ कंप्यूटर नहीं, सुविधा भी चाहिए...

ई-फाइलिंग और डिजिटल न्याय व्यवस्था ने अधिवक्ता के काम करने के तरीके को बदल दिया है। लेकिन डिजिटल व्यवस्था तभी प्रभावी होगी जब जिला और तहसील स्तर तक अधिवक्ता को आवश्यक तकनीकी सहायता उपलब्ध हो। इसलिए न्यायालय परिसर में अधिवक्ता डिजिटल सहायता केंद्र स्थापित किए जा सकते हैं,जहां ई-फाइलिंग,स्कैनिंग,प्रिंटिंग और ऑनलाइन न्यायालयीन सेवाओं से संबंधित तकनीकी सहायता उपलब्ध हो।

एक नया विचार—अधिवक्ता जीवन-चक्र कल्याण मॉडल

अधिवक्ता संरक्षण कानून को अलग-अलग योजनाओं का संग्रह बनाने के बजाय एकअधिवक्ता जीवन-चक्र कल्याण मॉडल के रूप में विकसित किया जा सकता है। इस मॉडल में अधिवक्ता के पेशेवर जीवन के पांच चरणों को ध्यान में रखा जाए...

प्रवेश : नए अधिवक्ता को प्रशिक्षण एवं छात्रवृत्ति।

स्थापना : कार्यस्थल,चेंबर और डिजिटल सुविधाएं।

सुरक्षा : कार्यस्थल पर हिंसा, धमकी और पेशेवर दबाव से कानूनी संरक्षण।

संकट : बीमारी,दुर्घटना और अस्थायी कार्य-असमर्थता में सहायता।

वृद्धावस्था : 65 वर्ष के बाद पात्र अधिवक्ता के लिए पेंशन/जीवन-निर्वाह सहायता...

ऐसी संरचना अधिवक्ता कल्याण को एक बिखरी हुई सहायता प्रणाली के बजाय दीर्घकालीन नीति का रूप दे सकती है।

विशेष मांग-पत्र : प्रस्तावित प्रमुख बिंदु

- अधिवक्ता के चेंबर,कार्यालय अथवा न्यायालय परिसर में मारपीट,धमकी, गाली-गलौज एवं पेशेवर कार्य में जबरन हस्तक्षेप के लिए विशेष कानूनी प्रावधान।
- गंभीर प्रकृति की घटनाओं में परिस्थितियों के अनुरूप गैर-जमानती प्रावधानों पर विधायी विचार।
- तीन वर्ष से कम अवधि से पंजीकृत नएअधिवक्ताओं के लिए इंटर्नशिप/ प्रशिक्षण छात्रवृत्ति।
- 65 वर्ष से अधिक आयु के पात्र अधिवक्ताओं के लिए मासिक पेंशन या जीवन-निर्वाह सहायता।
- अधिवक्ता एवं आश्रित परिवार के लिए कम से कम 20 लाख रुपये तक कैशलेस चिकित्सा सुविधा।
- गंभीर बीमारी अथवा प्रमाणित कार्य-असमर्थता के दौरान निर्धारित अवधि के लिए जीवन-निर्वाह सहायता।
- आकस्मिक मृत्यु की स्थिति में पात्र अधिवक्ता के परिवार के लिए पर्याप्त आर्थिक सहायता।
- प्रत्येक न्यायालय में अधिवक्ताओं के लिए पर्याप्त बैठने की व्यवस्था और बार रूम।
- चेंबर/केबिन तथा मुवक्किल से कानूनी परामर्श के लिए प्राइवेट स्पेस।
- महिला अधिवक्ताओं के लिए आवश्यक सुरक्षित एवं सुविधाजनक कार्यस्थल।
- ई-फाइलिंग और अन्य डिजिटल सेवाओं के लिए अधिवक्ता सुविधा केंद्र।
- जरूरतमंद अधिवक्ताओं के बच्चों के लिए शिक्षा सहायता।
- गंभीर दुर्घटना एवं आकस्मिक परिस्थितियों के लिए आपातकालीन सहायता कोष।
- अधिवक्ता सुरक्षा संबंधी शिकायतों के लिए स्पष्ट, पारदर्शी और समयबद्ध प्रक्रिया।

अंतिम बात : संरक्षण का मतलब विशेषाधिकार नहीं, काम करने की स्वतंत्रता है

अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट की सबसे महत्वपूर्ण कसौटी यह नहीं होनी चाहिए कि उसमें कितनी धाराएं हैं। असली प्रश्न यह है कि क्या कानून अधिवक्ता को बिना भय,बिना अनुचित दबाव और सम्मानजनक परिस्थितियों में अपने पेशेवर दायित्व निभाने का वास्तविक वातावरण देता है।

सुरक्षा के साथ सामाजिक सुरक्षा जुड़नी चाहिए। नए अधिवक्ता को शुरुआत का सहारा चाहिए,वरिष्ठ अधिवक्ता को वृद्धावस्था की सुरक्षा चाहिए,बीमार अधिवक्ता को उपचार और आय दोनों की चिंता से राहत चाहिए और न्यायालय में काम करने वाले प्रत्येक अधिवक्ता को बैठने तथा मुवक्किल से गोपनीय बातचीत करने के लिए उचित स्थान चाहिए।

इसीलिए छत्तीसगढ़ में अधिवक्ता संरक्षण पर होने वाली चर्चा को केवल मारपीट के बाद कार्रवाई तक सीमित न रखकर पूरे पेशेवर जीवन की सुरक्षा के रूप में देखा जाना चाहिए।

यह दृष्टिकोण अधिवक्ता को कोई विशेषाधिकार देने की बात नहीं करता। इसका उद्देश्य इतना भर है कि जो व्यक्ति दूसरों के अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय में खड़ा होता है,उसके अपने सुरक्षित कार्यस्थल,स्वास्थ्य,सम्मान और सामाजिक सुरक्षा के प्रश्न भी नीति-निर्माण में पर्याप्त महत्व प्राप्त करें। अधिवक्ता साथी हमारे इस मुहिम से जुड़ने के लिए संपर्क करे

यूपीआई पर शुल्क की आहट,डिजिटल भरोसे की अग्निपरीक्षा

पैसा नहीं,भरोसा है यूपीआई की सबसे बड़ी पूंजी...

जिस यूपीआई ने भारत में भुगतान की आदत बदल दी,अब उसी यूपीआई की अर्थव्यवस्था बदलने जा रही है। मोबाइल निकाला,क्यूआर कोड स्कैन किया और भुगतान हो गया,न नकदी की जरूरत,न खुले पैसे की चिंता और न किसी अतिरिक्त शुल्क का झंझट। चाय की दुकान से लेकर मॉल तक,रेहड़ी-पटरी वाले से लेकर बड़े कारोबारी प्रतिष्ठानों तक यूपीआई भारतीय जीवन का हिस्सा बन चुका है। ऐसे में 15 अक्टूबर से 2,000 रुपये से अधिक के चुनिंदा पर्सन-टू-मर्चेंट (पी2एम) लेन-देन पर 0.4 प्रतिशत मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) लागू करने का निर्णय केवल भुगतान उद्योग का व्यावसायिक निर्णय नहीं है बल्कि यह भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था के भविष्य से जुड़ा सवाल है। इसलिए पहले सभी प्रकार के भ्रम दूर होने चाहिएं। फिलहाल ग्राहक के बैंक खाते से 0.4 प्रतिशत शुल्क नहीं कटेगा,यह एमडीआर व्यापारी से लिया जाना है। 2,000 रुपये तक के पी2एम लेन-देन इससे बाहर रहेंगे और पर्सन-टू-पर्सन यानी पी2एम भुगतान राशि की परवाह किए बिना मुफ्त रहेंगे। सरकार के अनुसार लगभग 96 प्रतिशत पी2एम लेन-देन भी इस व्यवस्था से प्रभावित नहीं होंगे। 75,000 रुपये या उससे अधिक के पात्र लेन-देन पर एमडीआर की अधिकतम सीमा 300 रुपये होगी। अर्थात आज की स्थिति में यह कहना गलत होगा कि 2,000 रुपये

योगेश कुमार गोयल
नजफगढ़,नई दिल्ली

से ज्यादा का यूपीआई भुगतान करने पर ग्राहक को सीधे 0.4 प्रतिशत देना पड़ेगा। यहीं से एक बड़ा सवाल जन्म लेता है कि क्या किसी शुल्क का ग्राहक से सीधे न लिया जाना यह गारंटी देता है कि उसका अंतिम आर्थिक बोझ ग्राहक तक नहीं पहुंचेगा? इसका उत्तर बाजार के व्यवहार में छिपा है। व्यापारी से शुल्क लिया जाएगा तो वह इसे अपने खर्च में जोड़ेगा। कोई व्यापारी अपना मार्जिन घटाकर लागत वहन कर सकता है, कोई वस्तु या सेवा की कीमत में उसे समायोजित कर सकता है और कोई ग्राहक को नकद भुगतान की ओर आकर्षित कर सकता है। यूपीआई की असली ताकत उसकी तकनीक भर नहीं है बल्कि उसकी असली ताकत उसकी सहजता,गति और कम लागत है। यदि भुगतान से पहले नागरिक को यह सोचना पड़े कि कौनसा माध्यम सस्ता है,किस राशि पर शुल्क लगेगा और व्यापारी उससे कितना अतिरिक्त पैसा मांगेगा तो डिजिटल भुगतान की सरलता पर चोट होगी। यहां सरकार के सामने एक वास्तविक चुनौती भी है। माना कि इतना विशाल भुगतान नेटवर्क मुफ्त में नहीं चलता। लगातार बढ़ते लेन-देन के साथ सर्वर, नेटवर्क, साइबर सुरक्षा, धोखाधड़ी रोकथाम, तकनीकी रखरखाव और डिजिटल अवसंरचना पर भारी खर्च होता है। वर्षों तक यूपीआई पर शून्य एमडीआर की व्यवस्था में इस लागत का बड़ा हिस्सा बैंक,भुगतान कंपनियां और सरकार वहन करते रहे हैं। इसलिए यूपीआई को आर्थिक रूप से टिकाऊ बनाने के लिए कोई मॉडल तलाशना अपने आप में गलत नहीं है। लेकिन टिकाऊपन के नाम पर जनता की जेब को स्थायी राजस्व स्रोत बना देना भी स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। यहीं बर्नस्टीन का अनुमान महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके आकलन के अनुसार, यदि यूपीआई के कुल ट्रांजैक्शन मूल्य के आधे हिस्से पर 40 बेसिस प्वाइंट यानी 0.4 प्रतिशत एमडीआर लगाया जाए तो वित्त वर्ष 2028 तक लगभग 22,000 करोड़ रुपये का वार्षिक राजस्व पूल बन सकता है। उसके अनुमान के अनुसार, इसमें बैंकों और भुगतान ऐप्स की हिस्सेदारी भी बड़ी होगी। यह कोई सरकारी राजस्व अनुमान नहीं बल्कि एक बाजार विश्लेषण है लेकिन यह जरूर बताता है कि यूपीआई अब केवल सुविधा नहीं बल्कि बहुत बड़ा आर्थिक पारिस्थितिकी तंत्र बन चुका है। यूपीआई के आंकड़े इसकी ताकत बताते हैं। 2016-17 में जहां यूपीआई लेन-देन लगभग दो करोड़ थे और उनका मूल्य करीब 7,000 करोड़ रुपये था,वहीं 2025-26 में लेन-देन बढ़कर लगभग 24,162 करोड़ और कुल मूल्य करीब 314 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया। एक दशक में हुई यह छलांग बताती है कि यूपीआई अब भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ जैसी डिजिटल अवसंरचना बन चुका है और जब कोई व्यवस्था इतनी बड़ी हो जाए तो उसके नियमों में छोटा बदलाव भी बड़ा प्रभाव पैदा कर सकता है। संख्या के लिहाज से 2,000 रुपये से अधिक के भुगतान कुल लेन-देन में छोटा हिस्सा हो सकते हैं लेकिन उनकी कुल वैल्यू बहुत बड़ी है। यानी नीति निर्माताओं ने फिलहाल ऐसी श्रेणी चुनी है, जहां अपेक्षाकृत कम संख्या में लेन-देन से भुगतान नेटवर्क की लागत का बड़ा हिस्सा निकाला जा सकता है और रोजमर्रा के छोटे भुगतान को बचाया जा सकता है। यह संतुलन बनाए रखना ही असली चुनौती है। छोटे दुकानदार और रेहड़ी-पटरी वाले यूपीआई के सबसे बड़े लाभार्थियों में हैं। उनके लिए डिजिटल भुगतान सुविधा भी है और कारोबार बढ़ाने का माध्यम भी। यदि भुगतान स्वीकार करने की लागत बढ़ती है तो उसका असर उनके छोटे-छोटे मार्जिन पर पड़ सकता है। इसलिए छोटे व्यापारियों के लिए उपलब्ध छूट और सुरक्षा प्रावधानों का प्रभावी क्रियान्वयन अत्यंत आवश्यक है। दूसरी चिंता पारदर्शिता की है। यदि एमडीआर लागू हो रहा है तो जनता को यह साफ-साफ बताया जाना चाहिए कि उससे प्राप्त रकम का आर्थिक ढांचा क्या होगा, किस हिस्से से किस पक्ष की लागत पूरी होगी और भुगतान अवसंरचना को मजबूत करने में इसका कितना उपयोग होगा। जनता पर लागत डालने से पहले जनता को हिसाब मिलना चाहिए।

पत्नी प्रशंसा दिवस

20 सितंबर,2026 को पत्नी प्रशंसा दिवस बड़े उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। जब देश में अलग-अलग दिवस मनाये जाते हैं तो पत्नी प्रशंसा दिवस मनाया जाना घर गृहस्ती की खुशियों में चार चांद लगाने वाली बात है। हमारा पुरुष प्रधान समाज है जिसमें महिलाओं के मुकाबले में पुरुषों को ज्यादा महत्व दिया जाता है। शायद इसी बात को लेकर ही पत्नी प्रशंसा दिवस मनाया जाने लगा है। पति और पत्नी घर गृहस्ती की गाड़ी के दो पहिए हैं। आमतौर पर पुरुष वाला पहिया बाजी मार जाता है और पीछे रह जाती है बेचारी महिला। इस तरह से पत्नी प्रशंसा दिवस मनाया जाना महिलाओं के साथ न्याय करने वाली बात हो जाती है। कहा भी जाता है कि No Life Without Wife और बात भी सच है। परिवार में पत्नी का विशेष महत्व होता है। पत्नी मकान को घर बनाती है,पुरुष के खानदान को आगे बढ़ाने में मदद करती है,बच्चों की देखभाल करती है और उन्हें अच्छे संस्कार देती है,अपने पति की तथा ससुराल के अन्य सदस्यों की सेवा करती है। पत्नी के बिना बेचारा पति जीवन में अकेला रह जाता है। इन

प्रोफेसर शामलाल कौशल
रोहतक,हरियाणा

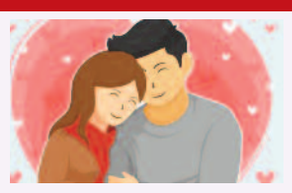

बातों को लेकर पत्नी की प्रशंसा किया जाना बहुत जरूरी हो जाता है। पत्नी प्रशंसा दिवस पर पत्नी के साथ मीठा बोलना चाहिए,उसके कामों की प्रशंसा करनी चाहिए,बाहर घूमाने के लिए ले जाना चाहिए, उसे उपहार दिए जाने चाहिए,तुम कितनी सुंदर हो, तुम्हारे बिना मेरा दिल नहीं लगता, तुम साक्षात देवी हो,आदि बातें कह कर उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। अगर पत्नी का व्यवहार परिवार के साथ ठीक रहे तो घर में सुख शांति का वास होता है और अगर यह देवी अपने असली रूप में आ जाए तो नौ देवियों के दर्शन भी करा सकती है। बेशक आजकल पतियों के मुकाबले में हर मामले में पत्नियां बाजी मारने लगी हैं,घर में कोई भी काम पत्नी की मर्जी के बिना नहीं हो सकता। इसके बावजूद भी पत्नी की प्रशंसा तो करनी ही चाहिए। आदमी आदमी है और औरत औरत है। दोनों का अपना-अपना महत्व है। मर्द की तो लोग हर बात को लेकर प्रशंसा करते हैं परंतु अधिकांश औरतों को घर में ही रहना पड़ता है,पति,सास ससुर तथा नंद के ताने सुनती हैं। कई बार पत्नियां नाराज होकर मायके जाने की धमकी देती हैं। ऐसे में बेचारा पति हाथ पैर जोड़कर उसे मना कर घर में ही रहने की प्रार्थना करता है। हमारे देश में 20 सितंबर को पत्नी प्रशंसा दिवस मनाया जाता है। वास्तव में पत्नी के कामों और महत्व को देखते हुए उसकी रोज ही प्रशंसा करनी चाहिए। सच पूछा जाए तो जो पत्नियां घर संभालने के साथ-साथ नौकरी भी करती हैं वह बहुत ज्यादा प्रशंसा की पात्र हैं। पत्नी की प्रशंसा में,पत्नी चालीसा,पत्नी की आरती,पत्नी की महिमा,आदि लिखा जाना चाहिए। आदमी तो छोड़िए देवता लोग भी अपनी पत्नी की प्रशंसा करते रहते हैं। कृष्ण जी राधा की,श्री रामचंद्र जी सीता की,कामदेव रति की प्रशंसा करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। यह पुरुष समाज का कर्तव्य है कि पत्नियों की इज्जत करें,उनके अधिकारों की रक्षा करें और उनके प्रति क्रूरता को रोकने की कोशिश करें। पति-पत्नी को परिवार में मिल जुल कर रहना चाहिए,एक दूसरे की आलोचना नहीं करनी चाहिए,एक दूसरे के काम में हाथ बटाना चाहिए, सोने से पहले दिन भर के गिले शिकवे दूर करके सोना चाहिए,एक दूसरे की प्रशंसा करनी चाहिए,किसी तीसरे में दिलचस्पी नहीं दिखानी चाहिए। पत्नी देवी है,पत्नी लक्ष्मी है, पत्नी दुर्गा है,पत्नी अर्धांगिनी है,पत्नी वंश बढ़ाने वाली है। ऐसे में बोलो,पत्नी देवी की जय।

सूचना

समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटिक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटारा अम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।

सम्पादक

प्रकाशक: दैनिक घटती-घटना

अग्र महाकुंभ-2026 का भव्य शुभारंभ

औद्योगिक नीति 2024-30 से प्रदेश में निवेश और रोजगार को नई गति

- अब तक 8.23 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त
- स्टार्टअप एवं निपुण मिशन के लिए 5 वर्षों में 500 करोड़ रुपए का प्रावधान
- सभी 33 जिलों में बनेंगे उद्यमिता विकास केंद्र
- महिला शक्ति और युवाओं की भागीदारी से समाज को मिलेगी नई ऊर्जा

"महाराजा अग्रसेन का संदेश है कि समाज की उन्नति तभी संभव है, जब हर व्यक्ति को आगे बढ़ने का अवसर मिले और सक्षम लोग जरुरतमंदों का हाथ थामें।
— श्री विष्णु देव साय
मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

निवेश और रोजगार को नई गति दे रही औद्योगिक नीति : सीएम साय

सीएम साय ने किया ट्रेड फेयर का शुभारंभ,स्टार्टअप एवं निपुण मिशन के लिए 500 करोड़ का प्रावधान,33 जिलों में स्थापित होंगे उद्यमिता विकास केंद्र

-संवाददाता-
अंबिकापुर,19 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने शनिवार को अंबिकापुर में आयोजित दो दिवसीय 'अग्र महाकुंभ-2026' का शुभारंभ किया, इस अवसर पर उन्होंने अग्रवाल समाज की उद्यमिता,दानशीलता,परोपकार और समाजसेवा की परंपरा की सराहना करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति में अग्रवाल समाज की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, उन्होंने कहा कि व्यापार और व्यवसाय के साथ समाज के उद्यमियों ने उद्योगों की स्थापना, रोजगार सृजन और जनसेवा के क्षेत्र में भी योगदान दिया है।

मुख्यमंत्री ने कहा... कि राज्य सरकार प्रदेश में ऐसा सुरक्षित,पारदर्शी और उद्योग

अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए कार्य कर रही है,जहां निवेश बढ़े, उद्योगों का विस्तार हो और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित हों, उन्होंने बताया कि राज्य को अब तक 8 लाख 23 हजार करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं,सरकार के अनुसार इन प्रस्तावों के धरातल पर उतरने से प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों का विस्तार होगा और रोजगार के नए अवसर तैयार होंगे।

महाराजा अग्रसेन के आदर्शों को आगे बढ़ाने का आह्वान-मुख्यमंत्री ने महाराजा अग्रसेन के सामाजिक आदर्शों का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने सामाजिक समानता, करुणा, सहयोग और सहभागिता पर आधारित समाज की कल्पना की थी। उनका संदेश था कि समाज की वास्तविक उन्नति तभी संभव है, जब प्रत्येक व्यक्ति को आगे बढ़ने का अवसर

मिले और सक्षम लोग जरूरतमंदों का हाथ थामकर उन्हें भी प्रगति की राह पर आगे बढ़ाएं, उन्होंने कहा कि अग्रवाल समाज ने इन आदर्शों को पीढ़ी-दर-पीढ़ी अपने आचरण में उतारा है, समाज की पहचान केवल व्यापार और आर्थिक सफलता तक सीमित नहीं है, बल्कि अर्थोपार्जन के साथ परमार्थ और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना भी इसकी विशिष्ट पहचान रही है, मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य शिविरों,धर्मशालाओं, शिक्षा एवं स्वास्थ्य संस्थाओं तथा अन्य जनसेवा गतिविधियों के माध्यम से समाज द्वारा किए जा रहे कार्यों का उल्लेख किया, उन्होंने कोरोना महामारी के दौरान जरूरतमंदों तक राशन पहुंचाने,ऑक्सीजन उपलब्ध कराने और स्वास्थ्य सेवाओं में सहयोग करने जैसी गतिविधियों को भी याद किया।

महिला शक्ति और युवाओं की भागीदारी पर जोर-मुख्यमंत्री ने अग्र महाकुंभ में महिला शक्ति को विशेष स्थान दिए जाने की सराहना करते हुए कहा कि महिलाएंअब परिवार की जिम्मेदारियों के साथ व्यापार, शिक्षा, चिकित्सा,उद्योग,स्टार्टअप और समाजसेवा सहित विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व कर रही हैं,उन्होंने कहा कि महिलाओं की बढ़ती भागीदारी परिवार और समाज के साथ प्रदेश की आर्थिक प्रगति को भी नई शक्ति प्रदान कर रही है, युवाओं को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि बदलते समय में नई पीढ़ी के सामने अवसरों का बड़ा संसार है, युवाओं को अपने संस्कारों और सामाजिक मूल्यों से जुड़े रहते हुए आधुनिक तकनीक, नवाचार और उद्यमिता को अपनाना चाहिए। उन्होंने युवाओं से केवल नौकरी तलाशने तक सीमित न रहने तथा नए विचारों और उद्यमों के माध्यम से स्वयं आगे बढ़ने के साथ दूसरों के लिए भी रोजगार के अवसर तैयार करने का आह्वान किया।

औद्योगिक नीति 2024-30 में रोजगार पर फोकस-मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की औद्योगिक नीति 2024-30 को रोजगार केंद्रित बनाया गया है,इसमें सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को प्रोत्साहन देने के साथ महिलाओं सहित विभिन्न वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं,प्रदेश में पर्यटन की संभावनाओं को देखते हुए पर्यटन को भी उद्योग का दर्जा दिया गया है,उन्होंने बताया कि युवाओं की उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 'मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं निपुण मिशन' को मंजूरी दी है,इसके लिए आगामी पांच वर्षों में 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, मिशन के तहत प्रदेश के सभी 33 जिलों में उद्यमिता विकास केंद्र स्थापित किए जाने की योजना है, इसके साथ ही 100 इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लैब और 5 इंडस्ट्री सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे,सरकार के अनुसार इससे युवाओं को नई तकनीक, कौशल, नवाचार और स्टार्टअप के क्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे।

निर्यात प्रोत्साहन नीति से स्थानीय उत्पादों को बाजार-मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026-30 को भी मंजूरी दी है,इसका उद्देश्य प्रदेश के छोटे उद्योगों,स्थानीय उत्पादों तथा मूल्य संवर्धित कृषि एवं औद्योगिक उत्पादों को देश और विदेश के बड़े बाजारों से जोड़ना है,उन्होंने कहा कि इससे स्थानीय उद्यमियों के लिए नए बाजार खुलने और छत्तीसगढ़ के उत्पादों को व्यापक पहचान मिलने की संभावनाएं बढ़ेंगी।

ट्रेड फेयर का शुभारंभ,अग्रकुल दर्शन पत्रिका का विमोचन-मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अग्र महाकुंभ के अवसर पर कार्यक्रम स्थल पर लगाए गए ट्रेड फेयर का फीता काटकर शुभारंभ किया,उन्होंने विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन किया और उद्यमियों से उनके उत्पादों तथा गतिविधियों की जानकारी ली,इस दौरान मुख्यमंत्री ने अग्रकुल दर्शन पत्रिका का विमोचन भी किया।

मंत्री राजेश अग्रवाल बोले...समृद्धि का अर्थ सबको आगे बढ़ाना-पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि अग्र महाकुंभ सामूहिक चेतना,संगठन शक्ति,सामाजिक उत्तरदायित्व और भविष्य की दिशा पर विचार करने का महत्वपूर्ण अवसर है,उन्होंने कहा कि महाराजा अग्रसेन ने जिस सामाजिक व्यवस्था की कल्पना की थी,उसके मूल में समानता, सहयोग,संवेदनशीलता और सहभागिता की भावना थी।

स्वास्थ्य और योग को भी महाकुंभ में स्थान-मुख्यमंत्री ने अग्र महाकुंभ में स्वास्थ्य और योग जैसे विषयों को शामिल किए जाने की भी सराहना की,उन्होंने कहा कि व्यापार और कार्य की व्यस्तता के बीच स्वास्थ्य की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए,स्वस्थ व्यक्ति से स्वस्थ परिवार और स्वस्थ समाज का निर्माण होता है तथा स्वस्थ समाज ही निरंतर प्रगति की दिशा में आगे बढ़ सकता है,मुख्यमंत्री ने कहा कि अग्रवाल समाज की उद्यमिता,सेवा,सहयोग और परोपकार की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में समाज महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

ये रहे मौजूद-कार्यक्रम में सरगुजा सांसद चिंतामणी महाराज, बसना विधायक संपत अग्रवाल,छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष संजय अग्रवाल,पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल, पूर्व कैबिनेट मंत्री अमर अग्रवाल,अंबिकापुर नगर निगम महापौर मंजूषा भगत,निगम सभापति हरमिंदर सिंह टिन्नी,भारत सिंह सिसोदिया,कलेक्टर अजीत वसंत,वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश अग्रवाल,नगर पुलिस अधीक्षक राहुल बंसल,जिला पंचायत सीईओ रोमा श्रीवास्तव,नगर निगम आयुक्त विनय कुमार अग्रवाल सहित अग्रवाल समाज के राष्ट्रीय एवं प्रांतीय स्तर के पदाधिकारी, समाजसेवी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।

सरगुजा में पर्यटन और स्थानीय उद्योगों की संभावनाएं...

मुख्यमंत्री ने सरगुजा अंचल की आर्थिक संभावनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि क्षेत्र में पर्यटन,कृषि आधारित उद्योग,खाद्य प्रसंस्करण और स्थानीय उत्पादों के क्षेत्र में व्यापक संभावनाएं मौजूद हैं,पर्यटन को उद्योग का दर्जा मिलने के बाद होटल,होम-स्टे और पर्यटन सेवाओं से जुड़े क्षेत्रों में निवेश एवं रोजगार के अवसर विकसित हो रहे हैं,उन्होंने अग्रवाल समाज के अनुभवी उद्यमियों से इन क्षेत्रों से जुड़ने तथा अपने अनुभव के माध्यम से युवाओं और छोटे उद्यमियों को आगे बढ़ाने में सहयोग करने का आह्वान किया।

दशम अग्र अलंकरण से प्रतिभाओं का सम्मान

मुख्यमंत्री ने 'दशम अग्र अलंकरण' के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की,उन्होंने कहा कि समाज की प्रतिभाओं का सम्मान नई पीढ़ी को अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, उन्होंने आयोजन से जुड़े छत्तीसगढ़ प्रांतीय अग्रवाल संगठन,अग्रवाल सभा अंबिकापुर,सरगुजा संभागीय अग्रवाल महासभा सहित सभी पदाधिकारियों और सदस्यों को अग्र महाकुंभ-2026 के आयोजन के लिए बधाई दी।

विद्यार्थियों ने पोस्टर,चित्रकला और भाषण के माध्यम से दिया सेवा,स्वच्छता व राष्ट्र निर्माण का दिया संदेश

-संवाददाता-
अंबिकापुर,19 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)।

एसएजीईएस ब्रम्हपारा अंबिकापुर में विद्यार्थियों में सेवा, समर्पण, सामाजिक उत्तरदायित्व और राष्ट्रहित की भावना विकसित करने के उद्देश्य से सेवा संकल्प अभियान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय की शाला प्रबंधन समिति (एसएमसी) के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष,पालकगण और विद्यालय परिवार के सदस्यों ने सहभागिता की। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलन से हुआ। इसके बाद विद्यार्थियों के लिए पोस्टर निर्माण,चित्रकला प्रतियोगिता और भाषण सहित विभिन्न रचनात्मक गतिविधियां आयोजित की गईं। इसमें 150 से अधिक विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। विद्यार्थियों ने सेवा, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक सद्भाव, शिक्षा, अनुशासन और राष्ट्र निर्माण जैसे विषयों पर अपने विचार रखे। पोस्टर और चित्रकला के माध्यम से भी उन्होंने समाज के प्रति अपने दायित्व और सेवा भावना को अभिव्यक्त किया। कार्यक्रम में उपस्थित एसएमसी पदाधिकारियों और पालकों ने विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया। अतिथियों ने विद्यार्थियों की रचनात्मक प्रतिभा की सराहना करते हुए उन्हें समाज और राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों के निर्वहन के लिए प्रेरित किया। विद्यालय परिवार ने कहा कि सेवा संकल्प अभियान का उद्देश्य विद्यार्थियों में सेवा,संवेदना, सहयोग और जिम्मेदारी की भावना विकसित करना है। कार्यक्रम का समापन विद्यार्थियों और उपस्थित सदस्यों ने सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति संकल्प लेकर किया।

हंसपुर रामनरेश हत्याकांड में निलंबित एसडीएम करुण डहरिया समेत तीन को जमानत नहीं...

हाईकोर्ट ने कहा...मौजूदा चरण में रिहाई उचित नहीं,ट्रायल कोर्ट को शीघ्र सुनवाई की स्वतंत्रता

-संवाददाता-
बलरामपुर,19 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)।

बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के बहुचर्चित हंसपुर रामनरेश मौत मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने निलंबित तत्कालीन कुसमी एसडीएम करुण डहरिया समेत तीन आरोपियों को नियमित जमानत देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति राकेश मोहन पांडेय की एकलपीठ ने 17 सितंबर 2026 को तीन अलग-अलग आपराधिक अपीलों पर सुनवाई के बाद उन्हें खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि मामले के मौजूदा चरण में आरोपियों को नियमित जमानत पर रिहा करना उचित नहीं है।

15 फरवरी की रात हंसपुर में हुआ था विवाद : मामला 15 फरवरी 2026 की रात ग्राम हंसपुर के पास बॉक्साइट से लदे वाहन को ग्रामीणों द्वारा रोके जाने के बाद हुए विवाद से जुड़ा है। अभियोजन के अनुसार वाहन को लेकर विवाद के दौरान तत्कालीन

एसडीएम करुण डहरिया समेत अन्य आरोपियों और ग्रामीणों के बीच मारपीट हुई। घटना में कई लोग घायल हुए थे। घायलों में रामनरेश भी शामिल थे,जिनकी उपचार के दौरान अत्यधिक आंतरिक रक्तस्राव के कारण मौत हो गई। मामले में थाना कोरंधा में अपराध क्रमांक 03/2026 दर्ज किया गया। प्रकरण में भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के साथ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धाराएं भी लगाई गई हैं। पुलिस ने 16 फरवरी 2026 को आरोपियों को गिरफ्तार किया था। बाद में जांच पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

बचाव पक्ष ने लंबे समय से जेल में होने का दिया हवाला : जमानत याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से तर्क दिया गया कि आरोपी 16 फरवरी से जेल में हैं और पुलिस जांच पूरी कर आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है। इसलिए अब उन्हें नियमित जमानत का लाभ दिया जाना चाहिए। करुण डहरिया की ओर से यह भी तर्क रखा गया कि उन्हें हंसपुर और धनेशपुर क्षेत्र में अवैध बॉक्साइट खनन एवं परिवहन की सूचना मिली थी। बचाव पक्ष के अनुसार उन्होंने इसकी जानकारी कलेक्टर को दी थी और कलेक्टर के निर्देश पर मौके पर पहुंचे थे। बचाव पक्ष ने प्रशासनिक जांच रिपोर्ट का भी हवाला दिया।

राज्य पक्ष ने जमानत का किया विरोध : राज्य की ओर से जमानत का विरोध करते हुए कहा गया कि केस डायरी में दर्ज गवाहों के बयानों से अभियोजन के आरोपों को प्रथमदृष्टया समर्थन मिलता है। हाईकोर्ट के समक्ष यह भी बताया गया कि कुछ घायल व्यक्तियों और पुलिसकर्मियों के बयानों में आरोपियों द्वारा रामनरेश के साथ हाथ-मुक्कों से मारपीट किए जाने की बात सामने आई है।

कलेक्टर की जांच रिपोर्ट पर कोर्ट ने क्या कहा : बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत कलेक्टर की जांच रिपोर्ट को लेकर हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह रिपोर्ट पुलिस द्वारा प्रस्तुत आरोप पत्र का हिस्सा नहीं है। इसलिए जमानत के इस चरण में उसके आधार पर मामले के अभियोजन पक्ष के रिकॉर्ड को अलग तरीके से देखने का आधार नहीं बनता। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि जमानत पर सुनवाई के दौरान साक्ष्यों की विस्तृत जांच या गवाहों की विश्वसनीयता का अंतिम परीक्षण नहीं किया जा सकता। यह विषय मुकदमे के विचारण के दौरान तय होगा।

ड्यूटी के दौरान शराब पीकर डायल 112 वाहन दुर्घटनाग्रस्त करने वाला आरक्षक बर्खास्त

एसपी वैभव बैंकर ने की सख्त कार्रवाई, विभागीय जांच में आरोप प्रमाणित....

-संवाददाता-
बलरामपुर,19 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)।

डायल 112 जैसी आपातकालीन सेवा में ड्यूटी के दौरान शराब का सेवन कर शासकीय वाहन को दुर्घटनाग्रस्त करने के मामले में बलरामपुर पुलिस अधीक्षक वैभव बैंकर ने कड़ी कार्रवाई की है। विभागीय जांच में आरोप प्रमाणित पाए जाने के बाद आरक्षक क्रमांक 878 संजय मारकण्डे को पुलिस सेवा से पृथक कर दिया गया है। एसपी ने यह कार्रवाई 19 सितंबर 2026 को की।

7 जुलाई की रात हुआ था हादसा : मामला 7 जुलाई 2026 की रात का है। चौकी वाड्रफनगर,थाना बसंतपुर क्षेत्र में संचालित डायल 112 वाहन क्रमांक CG 03 A-2749 में आरक्षक संजय मारकण्डे

की ड्यूटी लगाई गई थी। रात करीब 11.40 बजे एक इवेंट की सूचना मिलने पर आरक्षक संजय मारकण्डे और वाहन चालक ओमप्रकाश यादव डायल 112 वाहन से ग्राम सिवरी बरतीकला की ओर रवाना हुए। बताया गया कि रवाना होने के कुछ ही देर बाद वाड्रफनगर-अंबिकापुर मुख्य मार्ग पर न्यू पंचवटी ढाबा के पास डायल 112 वाहन की सामने से आ रही पिकअप क्रमांक यूपी64 सीटी 1055 से भिड़ंत हो गई। दुर्घटना में शासकीय वाहन को काफी नुकसान पहुंचा।

मेडिकल जांच में शराब सेवन की पुष्टि : हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों और अधिकारियों को आरक्षक तथा चालक के व्यवहार से उनके नशे में होने का संदेह हुआ। इसके बाद दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र वाड्रफनगर ले जाकर चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया। पुलिस के अनुसार मेडिकल रिपोर्ट में दोनों के शराब के नशे में होने की पुष्टि हुई।

विभागीय जांच में गंभीर कदाचरण प्रमाणित : मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस विभाग ने विभागीय जांच शुरू की। जांच के दौरान ड्यूटी के समय शराब का सेवन करने,आपातकालीन सेवा के शासकीय वाहन में यात्रा करने तथा वाहन दुर्घटना में शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचने से जुड़े आरोपों की जांच की गई। विभागीय जांच में आरक्षक संजय मारकण्डे के विरुद्ध लगाए गए आरोप प्रमाणित पाए गए। पुलिस विभाग ने इसे कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही,अनुशासन हीनता और गंभीर कदाचरण माना।

19 सितंबर को सेवा से किया पृथक : जांच के निष्कर्षों के आधार पर बलरामपुर पुलिस अधीक्षक वैभव बैंकर ने 19 सितंबर 2026 को आरक्षक क्रमांक 878 संजय मारकण्डे,जो घटना के समय चौकी वाड्रफनगर में पदस्थ था और वर्तमान में रक्षित केंद्र बलरामपुर में पदस्थ था,को पुलिस सेवा से पृथक करने का आदेश जारी किया। पुलिस विभाग की इस कार्रवाई को ड्यूटी के दौरान अनुशासन और जिम्मेदारी को लेकर सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है।

सेवानिवृत्त जिला ऑडिटर विशेश्वर सोनी का निधन,20 सितंबर को होगा अंतिम संस्कार

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,19 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)।

शहर के मायापुर निवासी एवं समाज कल्याण विभाग में जिला ऑडिटर के पद से सेवानिवृत्त विशेश्वर सोनी का 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रहे थे। शनिवार को उनके निधन की खबर मिलते ही परिजनों, रिश्तेदारों और परिचितों में शोक की लहर दौड़ गई। स्व. विशेश्वर सोनी लंबे समय तक समाज कल्याण विभाग में अपनी सेवाएं देने के बाद जिला ऑडिटर के पद से सेवानिवृत्त हुए

थे। सेवानिवृत्ति के बाद वे मायापुर स्थित अपने निवास पर परिवार के साथ रह रहे थे। पिछले कुछ दिनों से स्वास्थ्य खराब होने के कारण उनका उपचार चल रहा था। इसी दौरान उनका निधन हो गया। वे नगर निगम अंबिकापुर के वरिष्ठ पार्षद विजय सोनी एवं मोहन सोनी के बड़े भाई तथा निमेष सोनी (मंटू) के पिता थे। उनके निधन की सूचना के बाद परिवार के साथ बड़ी संख्या में परिचितों एवं शुभचिंतकों ने शोक व्यक्त किया। परिजनों ने बताया कि स्व. सोनी का अंतिम संस्कार रविवार 20 सितंबर 2026 को सुबह 10 बजे शंकरघाट स्थित मुक्तिधाम में किया जाएगा। उनके निधन से परिवार में गहरा शोक व्याप्त है। परिजनों और परिचितों ने स्व. सोनी के निधन को अपूरणीय क्षति बताते हुए दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की।

CMYK

चरचा की 'लाइफलाइन' धंसी

25 हजार आबादी बेबस

स्कूल बसों के पहिए थमे | अस्पताल पहुंचना हुआ मुश्किल | रोजमर्रा की आवाजाही ठप | सवालों के घेरे में निर्माण एवं निगरानी व्यवस्था

अब धंसी पुलिया ने रोकी 25 हजार आबादी की राह

समय रहते नहीं जागा प्रशासन,स्कूल बसों से मरीजों तक सब बेहाल...

मुख्य मार्ग बंद,स्कूल बसों से मरीजों तक आवागमन प्रभावित,समय रहते मरम्मत नहीं होने पर प्रशासन की निगरानी पर सवाल...

हादसे का इंतजार करता रहा सिस्टम, अब धंसी चरचा की लाइफलाइन

चरचा की सड़क में बड़ा 'सुराख', प्रशासन की निगरानी पर सवाल...

सालभर पहले बना रेलवे अंडरब्रिज भी नहीं बचा! शिवपुर-चरचा मुख्य मार्ग बंद, स्कूल बसों के पहिए थमे

वैकल्पिक रास्ता भी जर्जर, प्रशासन की निगरानी और निर्माण गुणवत्ता पर बड़े सवाल...

-रवि सिंह-
बैकुंठपुर/कोरिया,19 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)।

जिस सड़क को चरचा क्षेत्र की करीब 25 हजार आबादी की लाइफलाइन कहा जाता है,वही सड़क अब एक धंसी हुई पुलिया के कारण बंद हो गई है, शिवपुर-चरचा मुख्य मार्ग पर स्थित रेलवे अंडरब्रिज की पुलिया शनिवार सुबह अचानक धंस गई,इसके साथ ही चरचा क्षेत्र का मुख्य संपर्क मार्ग बाधित हो गया और हजारों लोगों के सामने आवागमन का संकट खड़ा हो गया,स्कूल बसों की आवाजाही प्रभावित है,रोजमर्रा की जरूरतों का सामान लेकर आने-जाने वाले वाहनों पर असर पड़ा है और मरीजों तथा आपातकालीन सेवाओं को लेकर चिंता बढ़ गई है। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार यह अंडरब्रिज करीब एक वर्ष पहले ही निर्मित हुआ था,मामला सिर्फ पुलिया के धंसने तक सीमित नहीं है,असली सवाल यह है कि एक साल के भीतर ही महत्वपूर्ण मार्ग की पुलिया ऐसी स्थिति में कैसे पहुंच गई? यदि निर्माण के दौरान गुणवत्ता और तकनीकी मानकों का पालन हुआ था तो इतनी जल्दी संरचना के क्षतिग्रस्त होने की वजह क्या है? और यदि पुलिया की स्थिति पहले से कमजोर थी तो संबंधित एजेंसियों ने समय रहते निरीक्षण क्यों नहीं किया? अब पुलिया धंसने के बाद प्रशासनिक व्यवस्था सक्रिय होती दिखाई दे रही है, लेकिन जनता का सवाल इससे बड़ा है– क्या सरकारी तंत्र हमेशा किसी संरचना के टूटने का इंतजार करेगा और उसके बाद ही उसकी हालत देखने पहुंचेगा?

25 हजार लोगों का संपर्क प्रभावित-शिवपुर

चरचा मार्ग चरचा कॉलरी क्षेत्र को आसपास के प्रमुख मार्गों और राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है, इस मार्ग से स्कूल जाने वाले बच्चे, कर्मचारी,व्यापारी,मरीज और रोजमर्रा के काम से निकलने वाले लोग नियमित रूप से आवागमन करते हैं,पुलिया धंसने के बाद मुख्य मार्ग पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह प्रभावित हो गई है,स्कूल बसों के पहिए थमने की स्थिति बनी है। रोजाना सामान लेकर आने-जाने वाले वाहनों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है,एक पुलिया का क्षतिग्रस्त होना सामान्य तकनीकी घटना मानकर इसे टाला जा सकता है,लेकिन जब वही पुलिया 25 हजार लोगों के दैनिक आवागमन की प्रमुख कड़ी हो तो इसकी जिम्मेदारी और गंभीर हो जाती है।

सालभर में ही सवालों के घेरे में निर्माण

इस पूरे मामले का सबसे गंभीर पहलू यह है कि उपलब्ध रिपोर्टों के मुताबिक संबंधित रेलवे अंडरब्रिज करीब एक वर्ष पहले ही बनाया गया था,इतनी कम अवधि में महत्वपूर्ण संरचना के क्षतिग्रस्त होकर धंसने से निर्माण गुणवत्ता, तकनीकी निगरानी और रखरखाव पर सवाल उठना स्वाभाविक है,अगर संरचना नई थी तो उसकी तकनीकी मजबूती की जांच किस स्तर पर हुई थी? निर्माण के दौरान गुणवत्ता की निगरानी किसने की? निर्माण पूर्ण होने के बाद इसका निरीक्षण कब-कब किया गया? क्या बारिश,भारी वाहनों या अन्य दबाव के प्रभाव का आकलन किया गया था? और यदि पुलिया में पहले से कोई कमजोरी थी तो उसे समय रहते चिन्हित क्यों नहीं किया गया? इन सवालों का जवाब केवल निरीक्षण रिपोर्ट से नहीं,बल्कि जिम्मेदारी तय करने वाली कार्रवाई से मिलना चाहिए।

भारी कोयला परिवहन का दबाव भी चर्चा में-स्थानीय स्तर पर पुलिया पर भारी कोयला परिवहन और पिछले दिनों हुई बारिश के कारण बढ़े दबाव की बात सामने आई है,कुछ स्थानीय रिपोर्टों में भी भारी कोयला परिवहन को पुलिया की स्थिति से जोड़कर सवाल उठाए गए हैं,लेकिन इस बिंदु पर अंतिम निष्कर्ष तकनीकी जांच के बाद ही सामने आ सकता है,यही वजह है कि अब सबसे जरूरी कदम किसी एक कारण को मान लेना नहीं,बल्कि पुलिया के धंसने के वास्तविक कारणों की स्वतंत्र तकनीकी जांच कराना है,यदि भारी वाहनों का दबाव कारण है तो उसका आकलन होना चाहिए। यदि बारिश या जल निकासी समस्या है तो उसकी जांच होनी चाहिए। यदि निर्माण गुणवत्ता में कमी है तो संबंधित एजेंसी और जिम्मेदारों की जवाबदेही तय होनी चाहिए।

वैकल्पिक रास्ता भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं-मुख्य मार्ग बंद होने के बाद लोग वैकल्पिक रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार यह वैकल्पिक मार्ग भी पहले से खराब स्थिति में है,वहां मौजूद पुल जर्जर बताया गया है और सीसी सड़क भी कई स्थानों पर खराब है,मुख्य मार्ग बंद होने के बाद इस रास्ते पर वाहनों का दबाव बढ़ने से नई दुर्घटना का खतरा पैदा हो सकता है,यानी समस्या का तत्काल समाधान करने के लिए जिस वैकल्पिक रास्ते का सहारा लिया जा रहा है, उसकी अपनी स्थिति भी चिंता पैदा कर रही है, ऐसे में प्रशासन को केवल'वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है कहकर जिम्मेदारी पूरी करने के बजाय उसकी वास्तविक क्षमता और सुरक्षा का तकनीकी आकलन करना होगा।

हादसे के बाद जागने की बजाय पहले क्यों नहीं जागा तंत्र?-चरचा की पुलिया का धंसना प्रशासनिक निगरानी व्यवस्था के सामने सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा करता है कि यदि किसी संरचना में खतरा था तो उसका पता हादसे से पहले क्यों नहीं चला, सरकारी अधोसंरचना का मतलब केवल सड़क और पुल बनाना नहीं है,निर्माण के बाद उसका नियमित निरीक्षण और रखरखाव भी उतना ही महत्वपूर्ण है,अगर कोई पुलिया या पुल अपनी निर्धारित क्षमता से अधिक दबाव झेल रहा है, उसकी नींव या संरचना में कमजोरी है,जल निकासी ठीक नहीं है या सड़क के आसपास की मिट्टी कमजोर हो रही है, तो नियमित निरीक्षण में इन संकेतों की पहचान होनी चाहिए, लेकिन यहां स्थिति यह है कि जनता को मुख्य मार्ग बंद होने के बाद वैकल्पिक रास्ता तलाशना पड़ रहा है, यानी सरकारी व्यवस्था की निगरानी व्यवस्था वहां दिखाई नहीं दी,जहां उसे सबसे पहले दिखाई देना चाहिए था।

नेता प्रतिपक्ष लाल मुनि यादव ने सरकार पर साधा निशाना-पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष एवं वर्तमान नेता प्रतिपक्ष लाल मुनि यादव ने पुलिया के क्षतिग्रस्त होने को लेकर सरकार और प्रशासन पर निशाना साधा है,उन्होंने कहा कि शिवपुर-चरचा मुख्य मार्ग क्षेत्र की करीब 25 हजार आबादी के लिए महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग है,इसके बावजूद पुलिया की स्थिति को समय रहते गंभीरता से नहीं लिया गया, लाल मुनि यादव ने सवाल उठाया कि यदि पुलिया की स्थिति खराब थी तो समय रहते मरम्मत क्यों नहीं कराई गई और क्या प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा था,उन्होंने मरीजों और आपातकालीन सेवाओं को लेकर तत्काल वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराने की मांग की, साथ ही पुलिया का तकनीकी परीक्षण, मरम्मत अथवा पुनर्निर्माण तथा स्थायी समाधान होने तक सुरक्षित वैकल्पिक आवागमन की व्यवस्था करने की मांग रखी,उन्होंने कहा कि जनता को आश्वासन नहीं बल्कि तत्काल राहत और स्थायी समाधान चाहिए।

तकनीकी जांच से सामने आएगी असली तस्वीर-अब इस मामले में सबसे जरूरी कदम तकनीकी जांच है, पुलिया क्यों धंसी? निर्माण के समय कौन से तकनीकी मानक अपनाए गए? क्या निर्माण सामग्री और संरचना की गुणवत्ता की जांच हुई थी? पुलिया की भार वहन क्षमता कितनी थी? क्या भारी वाहनों के आवागमन का असर पड़ा? क्या जल निकासी व्यवस्था पर्याप्त थी? क्या निर्माण के बाद नियमित निरीक्षण हुआ? इन सवालों के जवाब तकनीकी जांच के बिना नहीं मिल सकते, इसलिए केवल जेसीबी लगाकर रास्ता खोल देना स्थायी समाधान नहीं होगा। पहले यह पता लगना जरूरी है कि संरचना विफल क्यों हुई।

जिम्मेदारी तय होगी या मामला मरम्मत तक सीमित रहेगा?-हर सरकारी निर्माण के बाद उसकी गुणवत्ता और सुरक्षा की जिम्मेदारी संबंधित एजेंसियों की होती है,यदि जांच में निर्माण संबंधी खामी सामने आती है तो केवल पुलिया की मरम्मत करना पर्याप्त नहीं होगा, जिम्मेदारी भी तय करनी होगी,क्योंकि यदि एक साल पुरानी संरचना तकनीकी रूप से विफल हो जाती है और उसके बाद केवल मरम्मत कराकर रास्ता खोल दिया जाता है,तो भविष्य में ऐसी घटना दोबारा होने की आशंका बनी रहेगी,जनता का सवाल इसलिए सिर्फ यह नहीं है कि पुलिया कब बनेगी? सवाल यह भी है कि पुलिया इस हालत में पहुंची क्यों?

सरकार के सामने अब दोहरी चुनौती-एक तरफ तत्काल आवागमन बहाल करना जरूरी है,दूसरी तरफ पुलिया के धंसने की वजह का पता लगाना भी उतना ही जरूरी है,तत्काल राहत के लिए सुरक्षित वैकल्पिक मार्ग को दुरुस्त करना होगा,स्कूल बसों और एंबुलेंस के लिए प्राथमिकता व्यवस्था बनानी होगी,दूसरी ओर पुलिया का तकनीकी परीक्षण कराकर यह तय करना होगा कि मरम्मत पर्याप्त है या पूरा पुनर्निर्माण आवश्यक है,यदि संरचना को केवल ऊपर से ठीक कर दिया गया और मूल तकनीकी समस्या बनी रही तो कुछ समय बाद फिर वही स्थिति पैदा हो सकती है।

चरचा पूछ रहा है...लाइफलाइन की निगरानी कौन करेगा?-चरचा की करीब 25 हजार आबादी के सामने फिलहाल सबसे बड़ा सवाल आवागमन का है,लेकिन इस घटना ने उससे भी बड़ा सवाल सरकारी व्यवस्था के सामने खड़ा किया है,क्या महत्वपूर्ण सड़कों और पुल-पुलियों की नियमित तकनीकी निगरानी होती है? क्या खराब होती संरचनाओं की सूची बनाकर समयबद्ध मरम्मत कराई जाती है? क्या निर्माण पूरा होने के बाद उसकी गुणवत्ता और सुरक्षा की वास्तविक जांच होती है? और अगर होती है तो एक साल के भीतर पुलिया के धंसने की नौबत कैसे आई? इन सवालों का जवाब अब सिर्फ अधिकारियों के बयान से नहीं,बल्कि दस्तावेजी और तकनीकी जांच से सामने आना चाहिए, फिलहाल शिवपुर-चरचा की लाइफलाइन बंद है, स्कूल बसों के पहिए प्रभावित हैं,रोजमर्रा का आवागमन बाधित है और मरीजों के लिए रास्ते को लेकर चिंता बनी हुई है,उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने वैकल्पिक मार्ग को सुगम बनाने के लिए मौके पर हस्तक्षेप भी किया है,अब जनता की नजर इस बात पर है कि प्रशासन सिर्फ गड्ढा भरकर रास्ता खोलता है या पुलिया के धंसने की जड़ तक पहुंचकर जिम्मेदारी भी तय करता है,क्योंकि चरचा को सिर्फ रास्ता नहीं चाहिए...उसे ऐसी सड़क और पुलिया चाहिए जिस पर अगली बारिश या अगला भारी वाहन गुजरते समय लोगों को यह डर न रहे कि सरकारी निर्माण फिर धंस जाएगा।

स्कूल बसों के पहिए थमे,बच्चों पर सीधा असर

मुख्य मार्ग बंद होने का सबसे तत्काल असर स्कूली बच्चों पर पड़ा है। स्कूल बसों की आवाजाही प्रभावित होने से बच्चों और अभिभावकों के सामने परेशानी खड़ी हो गई है,यह स्थिति केवल एक-दो दिन की यातायात समस्या नहीं है,यदि पुलिया की मरम्मत या पुनर्निर्माण में लंबा समय लगता है तो स्कूल जाने वाले बच्चों,कर्मचारियों और दैनिक यात्रियों के लिए लगातार वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी,ऐसे में प्रशासन को यह स्पष्ट करना चाहिए कि स्थायी समाधान तक स्कूल बसों और छोटे वाहनों के लिए सुरक्षित आवागमन कैसे सुनिश्चित किया जाएगा।

मरीजों के लिए सबसे बड़ा खतरा

किसी सड़क या पुलिया के बंद होने का वास्तविक महत्व तब समझ आता है जब किसी मरीज को अस्पताल पहुंचाने की जरूरत पड़ती है,आपात स्थिति में एंबुलेंस को यदि खराब या लंबा वैकल्पिक रास्ता लेना पड़े तो हर अतिरिक्त मिनट महत्वपूर्ण हो सकता है,चरचा क्षेत्र की बड़ी आबादी इस मार्ग पर निर्भर है,इसलिए स्वास्थ्य सेवाओं की निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए,सवाल सीधा है...यदि रात के समय कोई गंभीर मरीज फंस गया तो एंबुलेंस किस रास्ते से जाएगी? क्या वैकल्पिक मार्ग एंबुलेंस के लिए पर्याप्त सुरक्षित और सुगम है? क्या वहां यातायात नियंत्रण की व्यवस्था है? क्या प्रशासन ने इसकी आपातकालीन योजना तैयार की है? इन सवालों का जवाब जनता को चाहिए।

अच्छे रिटर्न का झांसा देकर महिला लेक्चरर से 55 लाख की ठगी

सहकर्मी लेक्चरर समेत पांच लोगों पर आरोप,46.12 लाख का बैंक लोन लेकर ट्रेडिंग कंपनी में कराया निवेश,अब किश्त के लिए नोटिस

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,19 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)।

शहर के गर्ल्स स्कूल की एक महिला लेक्चरर से ट्रेडिंग कंपनी में निवेश के नाम पर करीब 55 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। आरोप है कि अच्छे रिटर्न और बैंक लोन की किश्त कंपनी द्वारा चुकाने का झांसा देकर स्कूल की ही एक महिला लेक्चरर समेत अन्य लोगों ने निवेश कराया। पीड़िता ने कोतवाली थाने में जिला स्काउट गाइड अधिकारी समेत पांच लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार अंबिकापुर गर्ल्स स्कूल में पदस्थ लेक्चरर निर्मला मिंज ने पुलिस को बताया कि वर्ष 2023 में स्कूल की लेक्चरर संगीता राय तिर्की ने उन्हें एएसए ट्रेडिंग कंपनी में निवेश करने पर अच्छा रिटर्न मिलने की जानकारी दी थी। इसके बाद संगीता ने उनकी मुलाकात जिला स्काउट गाइड अधिकारी योगेश विश्वकर्मा से कराई। आरोप है कि योगेश ने कंपनी में निवेश से होने वाले फायदे की जानकारी देते हुए बताया कि विभागीय पे-स्लिप के आधार पर बैंक से आसानी से लोन स्वीकृत हो जाएगा। बैंक की किश्त कंपनी की ओर से जमा कराने का भी भरोसा दिया गया।

46.12 लाख का लोन लेकर किया निवेश : आरोप है कि झांसे में आकर निर्मला मिंज ने अलग-अलग बैंकों से 46 लाख 12 हजार रुपए का लोन लिया और रकम ट्रेडिंग कंपनी में निवेश कर दी। उन्हें बताया गया था कि कंपनी बैंक की मासिक किश्त जमा करेगी और इसके अलावा करीब 40 हजार रुपए मासिक लाभांश भी मिलेगा। कंपनी की ओर से किश्त जमा होती देखकर उन्हें भरोसा रहा कि उनका निवेश सुरक्षित है और बैंक का लोन भी चुकाया जा रहा है।

बैंक का नोटिस आया तो खुला मामला : करीब डेढ़ साल बाद निर्मला मिंज को बैंकों की ओर से करीब 9 लाख 27 हजार रुपए की बकाया किश्त जमा करने का नोटिस मिला। इसके बाद उन्होंने योगेश विश्वकर्मा और अन्य लोगों से संपर्क किया। आरोप है कि उन्हें बताया गया कि ट्रेडिंग कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज हो गया है,इसलिए रकम मिलने में समय लगेगा। इसके बाद उन्हें निवेश की रकम को लेकर स्थिति का पता चला।

पांच लोगों के खिलाफ रिपोर्ट : पीड़िता ने कोतवाली थाने में योगेश विश्वकर्मा, अरुण कुशवाहा,आकाश सिंह,शशिकांत सिंह और लेक्चरर संगीता राय तिर्की के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले की विवेचना शुरू कर दी है।

रसूलपुर हत्याकांड में पांचवां आरोपी गिरफ्तार

दामाद से पारिवारिक विवाद में ससुर की हत्या कराने का आरोप...चार आरोपी पहले ही जा चुके हैं जेल

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,19 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)।

शहर के रसूलपुर में 16 सितंबर को हुए वसीरुद्दीन सिद्दीकी हत्याकांड में पुलिस ने पांचवें आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार मामले में पारिवारिक विवाद और पुरानी रंजिश के चलते मृतक की हत्या की साजिश रची गई थी। घटना में शामिल चार आरोपियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज चुकी है। अब पांचवें आरोपी मोईन मियां को भी गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है।

मकान देखने के बहाने घर पहुंचे थे तीन लोग : पुलिस के अनुसार 16 सितंबर की सुबह करीब 10.15 बजे रसूलपुर स्थित सादिया शारीन सिद्दीकी के घर तीन अज्ञात व्यक्ति किराए का मकान देखने के बहाने पहुंचे थे। उस समय सादिया के पिता वसीरुद्दीन सिद्दीकी उनसे मकान के संबंध में बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान तीनों ने कथित तौर पर मिलकर उन पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में वसीरुद्दीन गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

तलाक का मामला बना विवाद की वजह : पुलिस के मुताबिक मृतक की बेटी सादिया शारीन सिद्दीकी का अपने पति मो. नाजिम शबा के साथ तलाक का मामला न्यायालय में चल रहा है। प्रार्थिया ने पुलिस को बताया था कि पूर्व में उसके पति द्वारा उसे और उसके मायके पक्ष के लोगों को केस वापस नहीं लेने पर जान से मारने की धमकी दी गई थी। इसी आधार पर पुलिस ने मामले की जांच आगे बढ़ाई। शुरुआत में पुलिस ने अपराध क्रमांक 647/26 के तहत बीएनएस की धारा 109(1), 3(5) तथा आर्म्स एक्ट की धारा 25, 27 के तहत अपराध दर्ज किया था। विवेचना के दौरान मामले में हत्या सहित अन्य धाराएं 103(1), 61(2) और 238 बीएनएस जोड़ी गई।

चार आरोपी पहले ही हैं गिरफ्तार

मामले की गंभीरता को देखते हुए डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा राजेश अग्रवाल के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रितेश चौधरी तथा नगर पुलिस अधीक्षक राहुल बंसल के नेतृत्व में कोतवाली पुलिस और साइबर सेल की टीम ने जांच शुरू की। फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल का निरीक्षण कर मौके से साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने जिले में नाकेबंदी और संदिग्धों की तलाश के साथ मामले में पूर्व में चार आरोपियों नाजिम शबा, कंचन कुमार, नेजारुद्दीन उर्फ गुड्डू तथा अवकाश साव उर्फ आकाश गुप्ता को गिरफ्तार किया था। चारों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है।

मरणासन्न कथन और गवाहों के बयान से मिला सुराग

विवेचना के दौरान मृतक के मरणासन्न कथन और प्रार्थिया सहित अन्य गवाहों के कथनों के आधार पर पुलिस को मोईन मियां की संलिप्तता के संबंध में जानकारी मिली। इसके बाद पुलिस ने मोईन मियां पिता स्व. रोजान असारी,उम्र 65 वर्ष, निवासी ग्राम सकलदीपा, पोस्ट चापीकला,थाना पाकी, जिला पलामू,झारखंड, हाल मुकाम रनपुर खुर्द सरनापारा,परसा,अंबिकापुर को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पुलिस के अनुसार पूछताछ और विवेचना में उसके विरुद्ध अपराध से संबंधित साक्ष्य मिलने के बाद उसे गिरफ्तार किया गया। आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है।

अन्य आरोपियों की तलाश जारी

पुलिस का कहना है कि मामले में शामिल अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है। संभावित ठिकानों पर दबिश के साथ पुलिस टीम लगातार उनकी पतासाजी कर रही है। अधिकारियों ने फरार आरोपियों को भी शीघ्र गिरफ्तार किए जाने की बात कही है।

CMYK

कौन संभालेगा बैकुंठपुर की कमान? भाजपा में दो दर्जन दावेदार, टिकट पर बढ़ी सियासी हलचल...

शैलेश-भानु के अनुभव से प्रशांत गुप्ता की नई सोच तक, भाजपा में टिकट को लेकर मंथन तेज

बैकुंठपुर में भाजपा का टिकट संग्राम में पुराने अनुभव पर भरोसा या युवाओं को मिलेगा मौका?

बैकुंठपुर भाजपा में टिकट की जंग में अनुभव बनाम युवा नेतृत्व, किसके नाम पर लगेगी मुहर?

भाजपा के सामने बड़ा सवाल...पुराने चेहरे या नई पीढ़ी? बैकुंठपुर अध्यक्ष पद पर दावेदारों की लंबी कतार

सीए प्रशांत गुप्ता समेत युवा चेहरों ने बढ़ाई दावेदारी, अनुभवी नेताओं के सामने नई चुनौती...

-रवि सिंह-

बैकुंठपुर, 19 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)।

दिसंबर 2026 में प्रस्तावित नगर पालिका चुनाव जैसे-जैसे करीब आता जा रहा है, बैकुंठपुर की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल चुनाव जीतने से पहले टिकट का बनता जा रहा है,खासकर भाजपा के भीतर नगर पालिका अध्यक्ष पद को लेकर दावेदारों की बढ़ती संख्या ने संगठन के सामने ऐसा राजनीतिक गणित खड़ा कर दिया है,जिसमें एक ओर वर्षों से नगर की राजनीति में सक्रिय अनुभवी चेहरे हैं तो दूसरी ओर नई पीढ़ी के युवा दावेदार अपनी राजनीतिक जमीन तलाशते हुए सामने आ रहे हैं। इस बार अध्यक्ष पद अनारक्षित होने की स्थिति ने दावेदारों के लिए मैदान और बड़ा कर दिया है। चर्चा है कि करीब दो दर्जन नाम अध्यक्ष पद की दौड़ में अपनी-अपनी संभावनाएं तलाश रहे हैं,इनमें लंबे समय से नगर पालिका की राजनीति में सक्रिय शैलेश शिवहरे और भानु पाल जैसे अनुभवी चेहरे हैं, तो दूसरी तरफ सीए प्रशांत गुप्ता,पत्रकार कमलेश शर्मा और शारदा गुप्ता जैसे नाम भी चर्चा में हैं,ऐसे में भाजपा के सामने केवल उम्मीदवार चुनने की चुनौती नहीं है। असली चुनौती यह होगी कि किस चेहरे को टिकट देकर पार्टी शहर में भविष्य की राजनीति का संदेश देना चाहती है,क्या भाजपा एक बार फिर उस चेहरे पर भरोसा करेगी जिसके पास नगर की राजनीति का लंबा अनुभव है? या फिर पार्टी यह मानकर आगे बढ़ेगी कि बदलते राजनीतिक माहौल में युवाओं को मौका देना ही आने वाले वर्षों की मजबूत राजनीतिक नींव तैयार कर सकता है? यही सवाल इस समय बैकुंठपुर की चुनावी चर्चा के केंद्र में है।

शैलेश शिवहरे की दावेदारी अनुभव,संगठन और नगर राजनीति का लंबा सफर...

भाजपा के संभावित दावेदारों की चर्चा शैलेश शिवहरे के नाम के बिना पूरी नहीं होती,नगर पालिका अध्यक्ष पद की राजनीति में उनका लंबा अनुभव रहा है,करीब 15 वर्षों से नगर पालिका अध्यक्ष पद की राजनीति में सक्रिय रहने वाले शैलेश शिवहरे अध्यक्ष पद का चुनाव दो बार लड़ चुके हैं,एक बार उन्हें जीत मिली तो एक बार हार का सामना करना पड़ा,यही लंबा राजनीतिक अनुभव उनकी सबसे बड़ी ताकत माना जा रहा है। नगर पालिका के कामकाज, स्थानीय समीकरण,वार्ड स्तर की राजनीति और संगठन के भीतर की राजनीतिक गतिविधियों से उनकी पुरानी पहचान है,लेकिन इस बार उनके सामने एक अलग तरह की चुनौती है, राजनीतिक चर्चा में यह भी कहा जा रहा है कि वे सार्वजनिक तौर पर अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने की इच्छा से इनकार करते दिखाई देते हैं, लेकिन अंदरूनी स्तर पर उनकी दावेदारी को पूरी तरह समाप्त नहीं माना जा रहा। यही वजह है कि उनके नाम को लेकर चर्चा लगातार बनी हुई है, इतना ही नहीं, उनके परिवार की ओर से भी राजनीतिक निरंतरता की तस्वीर सामने आती है,उनकी पत्नी के नाम को भी अध्यक्ष पद की संभावित दावेदारी के रूप में देखा जा रहा है,ऐसे में सवाल सिर्फ यह नहीं रह जाता कि शैलेश शिवहरे मैदान में उतरेंगे या नहीं, बल्कि सवाल यह भी है कि क्या परिवार की राजनीतिक सक्रियता नगर पालिका की राजनीति में आगे भी बनी रहेगी? भाजपा यदि अनुभव को प्राथमिकता देती है तो शैलेश शिवहरे का नाम स्वाभाविक रूप से मजबूत दावेदारों में रहेगा, लेकिन अगर पार्टी नई पीढ़ी को मौका देने की रणनीति बनाती है, तो यही लंबा राजनीतिक अनुभव इस बार उनके सामने चुनौती भी बन सकता है।

कमलेश शर्मा : पत्रकारिता के अनुभव से राजनीति में नई संभावना

दावेदारों में पत्रकार कमलेश शर्मा का नाम भी सामने आ रहा है,पत्रकारिता का अनुभव किसी भी शहर की राजनीति में एक अलग तरह की राजनीतिक पूंजी बन सकता है,पत्रकार के तौर पर शहर की समस्याओं,जनता के सवालों और स्थानीय प्रशासन की कार्यप्रणाली से लगातार जुड़ाव रहने के कारण उन्हें शहर की जमीनी समस्याओं की समझ होने का दावा किया जा सकता है,हालांकि चुनावी राजनीति और पत्रकारिता दोनों की प्रकृति अलग है। इसलिए उनकी दावेदारी का वास्तविक परीक्षण संगठन, जनता और चुनावी समीकरणों के स्तर पर ही होगा,फिर भी उनकी मौजूदगी भाजपा के भीतर यह संकेत देती है कि अध्यक्ष पद की दौड़ अब केवल पारंपरिक राजनीतिक चेहरों तक सीमित नहीं रह गई है।

भानु पाल भी मजबूत दावेदार,कई बार पार्षद रहने का अनुभव

दावेदारों की सूची में दूसरा प्रमुख नाम भानु पाल का है,वे कई बार पार्षद रह चुके हैं और नगर पालिका तथा भाजपा की राजनीति में उनका लंबा अनुभव है, अध्यक्ष पद के लिए उनकी दावेदारी का आधार भी यही राजनीतिक अनुभव है,लंबे समय तक वार्ड और नगर स्तर पर सक्रिय रहने के कारण उन्हें स्थानीय समस्याओं और राजनीतिक समीकरणों की समझ रखने वाला चेहरा माना जाता है,लेकिन यहां भी वही सवाल सामने आता है...क्या भाजपा इस बार अनुभव को प्राथमिकता देगी या अनुभव के साथ-साथ नई राजनीतिक ऊर्जा को महत्व देगी? भानु पाल जैसे पुराने राजनीतिक चेहरे के पक्ष में सबसे बड़ा तर्क यही हो सकता है कि नगर पालिका की जटिल राजनीति को समझने और उसे संभालने के लिए अनुभव जरूरी है,वहीं विरोधी तर्क यह हो सकता है कि यदि पार्टी हर बार पुराने चेहरों पर ही भरोसा करेगी तो नई पीढ़ी के लिए राजनीतिक नेतृत्व का रास्ता कब खुलेगा? यही द्वंद्व इस बार भाजपा के टिकट चयन को खास बना रहा है।

सीए प्रशांत गुप्ता: युवा चेहरे की दावेदारी ने बदला चुनावी विमर्श

भाजपा के संभावित दावेदारों में सीए प्रशांत गुप्ता का नाम इस पूरे समीकरण को सबसे ज्यादा अलग दिशा देता दिखाई देता है,प्रशांत गुप्ता की दावेदारी सिर्फ इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि वे युवा हैं,उनकी पहचान शिक्षित,पेशेवर और नई सोच वाले चेहरे के रूप में सामने आती है,उनके परिवार का भाजपा से पुराना जुड़ाव भी उनकी राजनीतिक दावेदारी को एक अलग आधार देता है, यही वजह है कि यदि भाजपा इस बार युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाने का निर्णय लेती है तो प्रशांत गुप्ता का नाम गंभीर विकल्प के तौर पर देखा जा सकता है,नगर राजनीति में लंबे समय से सक्रिय नेताओं के बीच किसी पेशेवर और युवा चेहरे का सामने आना अपने आप में एक राजनीतिक संदेश देता है, यह संदेश यह हो सकता है कि शहर को अब ऐसी राजनीति की जरूरत है जो केवल पारंपरिक राजनीतिक समीकरणों तक सीमित न रहे,बल्कि शहरी विकास, योजनाबद्ध कामकाज और भविष्य की जरूरतों को केंद्र में रखे,प्रशांत गुप्ता की दावेदारी का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यही है कि वे भाजपा के सामने पुराना अनुभव बनाम नई सोच का सवाल खड़ा करते हैं, अगर भाजपा का नेतृत्व यह मानता है कि आने वाले समय में नगर की राजनीति को युवा और शिक्षित नेतृत्व की जरूरत है,तो प्रशांत गुप्ता उस रणनीति के लिए उपयुक्त चेहरा हो सकते हैं, दूसरी ओर,यदि पार्टी का आकलन यह रहता है कि चुनावी राजनीति में पुराने संगठनात्मक नेटवर्क और लंबे अनुभव का कोई विकल्प नहीं है,तो फिर अनुभवी दावेदारों को प्राथमिकता मिल सकती है, इसलिए प्रशांत गुप्ता की दावेदारी को केवल एक और नाम मानना सही नहीं होगा,उनका नाम भाजपा के संभावित नेतृत्व परिवर्तन की बहस के केंद्र में है।

शारदा गुप्ता का नाम भी दावेदारों में...

भाजपा संगठन से जुड़ी शारदा गुप्ता का नाम भी अध्यक्ष पद के संभावित दावेदारों में चर्चा में है, संगठन से जुड़ाव किसी भी राजनीतिक दल में टिकट के लिए महत्वपूर्ण आधार माना जाता है, यदि भाजपा संगठनात्मक सक्रियता और पार्टी के भीतर लंबे समय के काम को महत्व देती है तो शारदा गुप्ता की दावेदारी भी समीकरण को प्रभावित कर सकती है,इस तरह देखा जाए तो भाजपा के सामने दावेदारों का एक ऐसा समूह है,जिसमें अनुभव,संगठन,युवा नेतृत्व,पेशेवर पृष्ठभूमि और स्थानीय पहचान...सभी तरह के विकल्प मौजूद हैं,यही विकल्पों की अधिकता अब भाजपा के लिए सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी चुनौती भी।

दो दर्जन नाम,लेकिन टिकट एक : असली परीक्षा अब शुरू

अध्यक्ष पद की दौड़ में करीब दो दर्जन नामों की चर्चा अपने आप में बताती है कि भाजपा के भीतर इस पद को लेकर कितनी राजनीतिक दिलचस्पी है, लेकिन राजनीति में दावेदारों की संख्या जितनी ज्यादा होती है,टिकट मिलने के बाद असंतोष की संभावना भी उतनी ही बढ़ती है,भाजपा के सामने इसलिए दो चरणों की चुनौती होगी,पहला–उम्मीदवार का चयन, दूसरा–उम्मीदवार चयन के बाद सभी दावेदारों और उनके समर्थकों को एकजुट करना,किसी एक चेहरे को टिकट मिलने के बाद बाकी दावेदारों की राजनीतिक भूमिका क्या होगी,यह चुनाव परिणाम पर सीधा असर डाल सकता है, अगर पार्टी टिकट वितरण के बाद सभी दावेदारों को एक मंच पर लाने में सफल रहती है तो दावेदारों की लंबी सूची भाजपा के लिए ताकत में बदल सकती है,लेकिन यदि टिकट के बाद असंतोष,भीतरघात या गुटबाजी सामने आती है तो यही लंबी सूची पार्टी के लिए मुश्किल भी बन सकती है।

युवा बनाम पुराने चेहरे : बैकुंठपुर में उठ रहा बड़ा सवाल

बैकुंठपुर की राजनीति में इस बार सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह दिखाई दे रहा है कि युवाओं में राजनीतिक नेतृत्व को लेकर उत्साह बढ़ा है,शहर का एक वर्ग चाहता है कि अब 50 वर्ष से कम उम्र के चेहरों को आगे आने का मौका मिले,नई पीढ़ी की यह इच्छा केवल किसी एक व्यक्ति के पक्ष में नहीं है,बल्कि इसे व्यापक राजनीतिक बदलाव की मांग के रूप में देखा जा रहा है,युवा दावेदारों की बढ़ती सक्रियता से उन पुराने नेताओं के लिए भी चुनौती पैदा हो रही है जो वर्षों से नगर की राजनीति में अपनी जगह बनाए हुए हैं,सवाल यह नहीं है कि पुराने नेता योग्य हैं या नहीं,सवाल यह है कि क्या पार्टी भविष्य के नेतृत्व के लिए अभी से नए चेहरों को तैयार करने का जोखिम उठाएगी? यही सवाल भाजपा के टिकट चयन को निर्णायक बना सकता है।

पटना नगर पंचायत का चुनाव बना राजनीतिक सबक?

बैकुंठपुर की चुनावी चर्चा में पटना नगर पंचायत के हालिया चुनाव का उदाहरण भी महत्वपूर्ण तरीके से सामने आ रहा है,स्थानीय राजनीतिक विश्लेषण के अनुसार वहां भाजपा को नए चेहरों को अवसर देने से लाभ मिला और कई पुराने राजनीतिक चेहरों को जनता ने स्वीकार नहीं किया, इसे भाजपा के भीतर इस बात के सबक के रूप में देखा जा रहा है कि केवल लंबे समय तक राजनीति करने वाला होना ही चुनाव जीतने की गारंटी नहीं है, मतदाता अब यह भी देखता है कि उम्मीदवार के पास नई सोच क्या है, शहर के विकास को लेकर उसका दृष्टिकोण क्या है और वह भविष्य की चुनौतियों से कैसे निपटेगा,यदि भाजपा इस उदाहरण को गंभीरता से लेती है तो बैकुंठपुर में भी टिकट चयन के दौरान युवा चेहरों की संभावना बढ़ सकती है, लेकिन यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि हर नगर की परिस्थितियां अलग होती हैं। इसलिए पटना के प्रयोग को हूबहू बैकुंठपुर में लागू करना भी आसान नहीं होगा, फिर भी यह उदाहरण भाजपा के सामने एक सवाल जरूर रखता है...क्या हर बार पुराने राजनीतिक समीकरण ही चुनाव जिताने के लिए पर्याप्त हैं?

टिकट किसी एक को,लेकिन चुनाव सभी को मिलकर लड़ना होगा

भाजपा की सबसे बड़ी परीक्षा टिकट घोषित होने के बाद होगी, करीब दो दर्जन दावेदारों में से एक को टिकट मिलेगा। बाकी को अपनी दावेदारी छोड़कर पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में खड़ा होना होगा,यहीं संगठन की असली क्षमता सामने आएगी,यदि शैलेश शिवहरे,भानु पाल,प्रशांत गुप्ता,कमलेश शर्मा,शारदा गुप्ता और अन्य संभावित दावेदारों के समर्थकों को पार्टी एकजुट करने में सफल रही तो टिकट विवाद चुनावी ताकत में बदल सकता है,लेकिन यदि टिकट के बाद दावेदारों के बीच असंतोष कायम रहा तो विपक्षी दलों को इसका फायदा उठाने का अवसर मिल सकता है,इसलिए उम्मीदवार चुनना भाजपा की पहली परीक्षा होगी और उम्मीदवार के पीछे पूरी पार्टी को खड़ा करना दूसरी और उससे भी बड़ी परीक्षा।

अब सवाल सिर्फ कौन जीतेगा का नहीं,किसे मौका मिलेगा का है...

बैकुंठपुर नगर पालिका चुनाव की राजनीति अब धीरे-धीरे उस मुकाम पर पहुंच रही है जहां हर दावेदार अपनी राजनीतिक संभावना तलाश रहा है,एक तरफ शैलेश शिवहरे का लंबा राजनीतिक अनुभव है। दूसरी तरफ भानु पाल की नगर राजनीति में सक्रियता है,वहीं सीए प्रशांत गुप्ता नई पीढ़ी,शिक्षा और पेशेवर सोच का चेहरा बनकर सामने आ रहे हैं, कमलेश शर्मा पत्रकारिता के अनुभव के साथ दावेदारी में हैं और शारदा गुप्ता संगठनात्मक आधार के साथ संभावित विकल्प हैं,इसके अलावा भी कई नाम टिकट की दौड़ में हैं, लेकिन अंतिम निर्णय में सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा कि भाजपा अतीत के अनुभव को प्राथमिकता देती है या भविष्य के नेतृत्व को, यदि पार्टी पुराने चेहरों पर भरोसा करती है तो चुनाव का संदेश होगा कि भाजपा अनुभव और स्थापित राजनीतिक नेटवर्क को अभी भी सबसे महत्वपूर्ण मानती है,अगर प्रशांत गुप्ता जैसे युवा चेहरे को अवसर मिलता है तो यह संदेश जाएगा कि पार्टी अब नगर की राजनीति में नई पीढ़ी को नेतृत्व सौंपने का प्रयोग करना चाहती है,और यदि किसी अन्य नए चेहरे पर दांव लगाया जाता है तो यह भी भाजपा की रणनीतिक सोच में बदलाव का संकेत माना जाएगा।

एमएलए फेस की राजनीति का असर नगर चुनाव पर कितना?

भाजपा की राजनीति में नेतृत्व चयन को लेकर बदलाव की चर्चा भी इस चुनाव में महत्वपूर्ण हो सकती है,स्थानीय स्तर पर यह बात कही जा रही है कि पार्टी अब कई जगहों पर पुराने समीकरणों से आगे बढ़कर नेतृत्व के नए चेहरों और बड़े राजनीतिक नेतृत्व के साथ तालमेल बैठाने वाले विकल्पों पर भी विचार कर रही है,यदि बैकुंठपुर में भी ऐसा प्रयोग होता है तो टिकट चयन में स्थानीय स्तर पर लंबे समय से प्रभाव रखने वाले चेहरों के बजाय अपेक्षाकृत नए चेहरे को अवसर मिल सकता है,यही स्थिति प्रशांत गुप्ता जैसे युवा दावेदारों के लिए राजनीतिक संभावना पैदा करती है, हालांकि अंतिम फैसला संगठन को ही करना है और अभी किसी नाम को आधिकारिक उम्मीदवार मानना जल्दबाजी होगी।

भाजपा के लिए चुनाव सिर्फ नगर पालिका का नहीं,जनमत का भी परीक्षण

भाजपा के सामने इस चुनाव का महत्व इसलिए भी बड़ा है क्योंकि पार्टी राज्य की सत्ता में है। ऐसे में नगर पालिका चुनाव को केवल स्थानीय चुनाव मानकर नहीं चलाया जा सकता,नगर की जनता सड़क,नाली, सफाई,पानी,प्रकाश,विकास कार्य और प्रशासनिक व्यवस्था जैसे मुद्दों पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों का मूल्यांकन करती है। इसलिए भाजपा जिस उम्मीदवार को मैदान में उतारेगी,उसके साथ पार्टी की सरकार और संगठन की छवि भी किसी न किसी रूप में जुड़ेगी,यही वजह है कि अध्यक्ष पद के उम्मीदवार का चयन केवल जातीय,व्यक्तिगत या पुराने राजनीतिक समीकरणों के आधार पर करने के बजाय जीतने की क्षमता,जनस्वीकार्यता, संगठनात्मक स्वीकार्यता और भविष्य के नेतृत्व के संतुलन से करना पार्टी के लिए महत्वपूर्ण होगा।

सबसे बड़ा सवाल : बैकुंठपुर में भाजपा का अगला चेहरा कौन?

दिसंबर का चुनाव अभी दूर है,लेकिन टिकट की राजनीति ने बैकुंठपुर में चुनावी तापमान बढ़ा दिया है,दावेदारों की बढ़ती संख्या ने भाजपा को एक ओर मजबूत विकल्प दिए हैं तो दूसरी ओर निर्णय को कठिन भी बना दिया है,शैलेश शिवहरे के पास अनुभव है,भानु पाल के पास लंबी नगर राजनीति है,प्रशांत गुप्ता के पास युवा और पेशेवर चेहरा होने की संभावना है,कमलेश शर्मा के पास शहर को देखने-समझने का पत्रकारिता अनुभव है और शारदा गुप्ता के पास संगठनात्मक जुड़ाव का आधार है,अब फैसला भाजपा को करना है कि वह इनमें से किस राजनीतिक संदेश के साथ चुनाव मैदान में उतरना चाहती है,क्या बैकुंठपुर में पुराने राजनीतिक अनुभव की वापसी होगी? क्या युवा चेहरों को अवसर देकर भाजपा नई राजनीतिक पारी शुरू करेगी? क्या सीए प्रशांत गुप्ता जैसे चेहरे को आगे बढ़ाकर पार्टी नई सोच और नई पीढ़ी का संदेश देगी? या फिर संगठन कोई ऐसा नाम सामने लाएगा जो इन सभी राजनीतिक समीकरणों को पीछे छोड़कर सभी गुटों को साथ लेकर चल सके? फिलहाल सबसे स्पष्ट बात यही है कि बैकुंठपुर नगर पालिका चुनाव में भाजपा के लिए असली मुकाबला विपक्ष से पहले अपने भीतर है,टिकट की दौड़ में जितने ज्यादा चेहरे हैं,उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी संगठन की है,एक गलत चयन असंतोष को जन्म दे सकता है और एक संतुलित चयन पूरे संगठन को चुनावी ताकत में बदल सकता है,इसलिए बैकुंठपुर में आने वाला नगर पालिका चुनाव केवल अध्यक्ष पद की कुर्सी का चुनाव नहीं माना जा रहा,यह भाजपा के लिए पुराने और नए नेतृत्व के बीच संतुलन,संगठन की निर्णय क्षमता और जनता के बदलते राजनीतिक मूड को समझने की परीक्षा भी बनने जा रहा है,अब नजर इस बात पर है कि भाजपा बैकुंठपुर को अपना अगला राजनीतिक चेहरा किसे बनाती है...अनुभव को, संगठन को या नई पीढ़ी की नई सोच को।

दो और 'सुपरमैन'! कोरिया की खाद्य सुरक्षा छोड़ नवा रायपुर की जिम्मेदारी कैसे संभलेगी?

कोरिया की खाद्य सुरक्षा या नवा रायपुर का अतिरिक्त प्रभार? एक अधिकारी...दो मोर्चे...

300 किमी दूर से डबल ड्यूटी! कोरिया की खाद्य जांच के बीच नवा रायपुर का अतिरिक्त प्रभार...

सैंपलिंग के बाद रिपोर्ट का इंतजार, अब अधिकारी संभालेंगे 300 किमी दूर का अतिरिक्त प्रभार...

खाद्य सुरक्षा की जमीन कमजोर, मुख्यालय का बोझ बढ़ा... एक अधिकारी,दो जिम्मेदारियां

जिले की शुद्धता जांच छोड़ेंगे या मुख्यालय संभालेंगे? अतिरिक्त प्रभार पर बड़ा सवाल...

जैसा चल रहा है,चलने दो वाला सिस्टम! कोरिया से नवा रायपुर तक अतिरिक्त प्रभार...

300 किलोमीटर दूर बैठे अधिकारी को मुख्यालय का अतिरिक्त प्रभार,जिस जिले में खाद्य पदार्थों की शुद्धता की जांच ही चुनौती बनी हुई वहां अब निगरानी और सैंपलिंग का क्या होगा?

-रवि सिंह-

कोरिया/बैकुंठपुर,19 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)।

सरकारी व्यवस्था में अतिरिक्त प्रभार कोई नई बात नहीं है,लेकिन जब एक अधिकारी को एक जिले की जिम्मेदारी के साथ सैकड़ों किलोमीटर दूर स्थित मुख्यालय की जिम्मेदारी भी सौंप दी जाए,तो सवाल केवल आदेश का नहीं,बल्कि जमीनी कामकाज की निगरानी का बन जाता है, 18 सितंबर 2026 को जारी शासन के आदेश ने इसी सवाल को जन्म दिया है। आदेश के अनुसार कोरिया जिले में पदस्थ अभिहित अधिकारी नीलम ठाकुर को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ नवा रायपुर स्थित नियंत्रक,खाद्य एवं औषधि प्रशासन कार्यालय में उप संचालक (खाद्य) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है,वहीं बेमेतरा के अभिहित अधिकारी आशीष कुमार यादव को भी उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ नवा रायपुर में उपायुक्त (खाद्य) का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, यानी विभाग ने दो अधिकारियों को उनके मौजूदा काम से हटाया नहीं है,बल्कि उसी जिम्मेदारी के साथ मुख्यालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी जोड़ दी है,यहीं से सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है–आखिर एक अधिकारी एक साथ कितनी जगह मौजूद रह सकता है?

कोरिया से नवा रायपुर तक जिम्मेदारी,बीच में कौन देखेगा जिला?–कोरिया कोई छोटा जिला नहीं है,यहां खाद्य पदार्थों की शुद्धता,मिलावट की जांच, सैंपलिंग और उससे जुड़ी कार्रवाई की जिम्मेदारी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की है,लेकिन जमीनी स्तर पर पहले से ही यह सवाल उठता रहा है कि खाद्य पदार्थों की नियमित जांच कितनी प्रभावी ढंग से हो रही है,स्थिति यह बताई जाती है कि शुद्धता और मिलावट की जांच के लिए कभी-कभी अभियान चलाया जाता है,कुछ दिनों तक कार्रवाई, सैंपलिंग और निरीक्षण की गतिविधियां दिखाई देती हैं और फिर कुछ समय बाद व्यवस्था पहले जैसी नजर आने लगती है,यानी सवाल यह नहीं कि अभियान चलता है या नहीं, बल्कि सवाल यह है कि क्या पूरे वर्ष नियमित रूप से खाद्य पदार्थों की जांच और निगरानी की व्यवस्था प्रभावी ढंग से चल रही है? अगर जिले में पहले से ही नियमित निगरानी को लेकर सवाल हैं, तो अब उसी अधिकारी के ऊपर नवा रायपुर की अतिरिक्त जिम्मेदारी डाल दिए जाने से यह सवाल और गंभीर हो जाता है।

'कुछ दिन अभियान,फिर सब सामान्य' वाली व्यवस्था?–जिले में खाद्य पदार्थों की शुद्धता जांच को लेकर यह धारणा बनती जा रही है कि जब कोई विशेष अभियान आता है तो विभाग सक्रिय दिखाई देता है, बाजारों में निरीक्षण होते हैं,सैंपल लिए जाते हैं और कार्रवाई की खबरें सामने आती हैं, लेकिन अभियान समाप्त होते ही नियमित निगरानी की रफ्तार पर सवाल उठने लगते हैं,यदि खाद्य सुरक्षा व्यवस्था अभियान आधारित होकर रह जाए तो मिलावट और अमानक खाद्य पदार्थों पर स्थायी नियंत्रण कैसे होगा? आम उपभोक्ता को तो रोज खाद्य सामग्री खरीदनी है। उसके लिए खाद्य सुरक्षा अभियान केवल कुछ दिनों का विषय नहीं है,दूध,मिठाई,मसाले,तेल,खाद्य सामग्री और अन्य उत्पादों की गुणवत्ता की जांच पूरे साल होनी चाहिए,यही कारण है कि जिले की खाद्य सुरक्षा व्यवस्था में नियमित निरीक्षण और लगातार निगरानी अधिक महत्वपूर्ण है।

सूत्रों का दावा...सेटिंग से चलता है सिस्टम,जांच की जरूरत–इसी बीच विभागीय कामकाज से जुड़े सूत्र गंभीर आरोप लगाते हैं,सूत्रों का दावा है कि कई मामलों में कार्रवाई की बजाय 'सेटिंग' का खेल चलता है और इसी वजह से व्यवस्था अपनी अपेक्षित कठोरता से काम नहीं कर पाती,हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि इस आदेश से नहीं होती है और इन्हें तथ्य के रूप में नहीं माना जा सकता, लेकिन यदि ऐसे आरोप लगातार सामने आ रहे हैं तो विभाग के लिए यह जांच का विषय जरूर होना चाहिए कि सैंपलिंग से लेकर रिपोर्ट,कार्रवाई और प्रकरण के अंतिम परिणाम तक पूरी प्रक्रिया कितनी पारदर्शी है,सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि यदि किसी खाद्य पदार्थ का नमूना मानक से बाहर पाया जाता है तो उसके बाद वास्तव में कितनी कार्रवाई होती है? सैंपल लेने से लेकर कार्रवाई पूरी होने तक की पूरी चेन सार्वजनिक क्यों नहीं होनी चाहिए?

अब मुख्यालय भी संभालेंगी,तो जिले की निगरानी कौन करेगा?–यही इस पूरे मामले का सबसे बड़ा सवाल है,कोरिया में अधिकारी की अपनी जिम्मेदारी बनी रहेगी और उसी के साथ नवा रायपुर में उप संचालक (खाद्य) का अतिरिक्त प्रभार भी रहेगा,शासन के आदेश में स्पष्ट रूप से वर्तमान कर्तव्यों के साथ अतिरिक्त प्रभार सौंपे जाने की बात कही गई है,ऐसे में प्रशासन को यह स्पष्ट करना चाहिए कि दोनों जिम्मेदारियों के बीच कार्य-विभाजन कैसे होगा,क्या कोरिया में नियमित निरीक्षण के लिए अलग अधिकारी या टीम उपलब्ध होगी? क्या सैंपलिंग की संख्या बढ़ाई जाएगी? क्या पुराने सैंपलों की रिपोर्ट और लंबित मामलों की समीक्षा होगी? क्या बाजारों में नियमित जांच होगी या फिर विशेष अभियान का इंतजार किया जाएगा? और सबसे महत्वपूर्ण–क्या अतिरिक्त प्रभार संभालने वाले अधिकारी को दोनों स्थानों की जिम्मेदारी प्रभावी ढंग से निभाने के लिए पर्याप्त प्रशासनिक सहयोग और मानव संसाधन उपलब्ध कराया जाएगा?

सुपरमैन चाहिए या मजबूत सिस्टम?–असल सवाल किसी अधिकारी की क्षमता पर नहीं है,सवाल सिस्टम की संरचना का है, एक सक्षम अधिकारी भी एक साथ कई जिम्मेदारियां संभाल सकता है,तकनीक ने काम को आसान बनाया है,लेकिन खाद्य सुरक्षा जैसे विभाग में केवल फाइलों का निपटारा पर्याप्त नहीं है,जमीन पर जाकर निरीक्षण करना,सैंपल लेना, उसकी जांच कराना,रिपोर्ट की समीक्षा करना और नियमों के मुताबिक कार्रवाई सुनिश्चित करना भी उतना ही जरूरी है, इसलिए व्यवस्था को किसी सुपरमैन अधिकारी पर निर्भर करने की बजाय ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जिसमें अधिकारी की अनुपस्थिति में भी जिला स्तर की खाद्य सुरक्षा निगरानी प्रभावित न हो,क्योंकि सवाल एक अधिकारी की कार्यक्षमता का नहीं, करोड़ों लोगों की थाली तक पहुंचने वाले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता का है।

शासन के सामने अब असली परीक्षा–18 सितंबर 2026 के आदेश में राज्य शासन ने दोनों अधिकारियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी है और आदेश उप सचिव विजय कुमार चौधरी के हस्ताक्षर से जारी हुआ है,आदेश की प्रतिलिपि खाद्य एवं औषधि प्रशासन के संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों तथा दोनों अधिकारियों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई है,अब जिम्मेदारी केवल आदेश जारी करने तक खत्म नहीं होती,असली परीक्षा यह होगी कि कोरिया की खाद्य सुरक्षा व्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ता है,यदि जिले में नियमित सैंपलिंग बढ़ती है,रिपोर्ट समय पर आती है,अमानक खाद्य पदार्थों पर कार्रवाई होती है और बाजारों में लगातार निगरानी दिखाई देती है तो अतिरिक्त प्रभार के बावजूद व्यवस्था मजबूत मानी जाएगी, लेकिन यदि अभियान कुछ दिनों तक चला, सैंपल लिए गए,फिर रिपोर्ट और कार्रवाई की प्रक्रिया ठंडी पड़ गई और अधिकारी मुख्यालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी में व्यस्त रहे तो सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर इस व्यवस्था का लाभ किसे मिला? क्योंकि कोरिया की जनता को अतिरिक्त प्रभार नहीं,सुरक्षित और शुद्ध खाद्य पदार्थ चाहिए,और यही वह बिंदु है जहां शासन को तय करना होगा कि उसे दो जगह का काम संभालने वाले सुपरमैन चाहिए या ऐसा मजबूत सिस्टम,जो किसी एक अधिकारी की मौजूदगी पर निर्भर न रहे।

सैंपल तो लिए जाते हैं,परिणाम का क्या?

खाद्य सुरक्षा व्यवस्था में सैंपलिंग सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया में से एक है। किसी खाद्य पदार्थ का नमूना लिया गया,उसे जांच के लिए भेजा गया और उसके बाद उसकी रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई हुई...तभी सैंपलिंग का वास्तविक उद्देश्य पूरा होता है,लेकिन जिले में सवाल यह भी उठ रहा है कि सैंपल लेने के बाद आगे क्या होता है? कितने सैंपल लिए गए? कितने सैंपल की रिपोर्ट आई? कितने नमूने मानक के अनुरूप नहीं मिले? कितने मामलों में कार्रवाई हुई? और कितने मामलों में मामला सिर्फ सैंपल लेने तक सीमित रह गया? इन सवालों के स्पष्ट और नियमित आंकड़े आम लोगों के सामने नहीं आने से व्यवस्था की प्रभावशीलता पर सवाल खड़े होते हैं,यही वजह है कि अब अतिरिक्त प्रभार का आदेश केवल प्रशासनिक आदेश नहीं रह जाता। यह सवाल भी सामने आता है कि जब जिले की नियमित निगरानी ही पूरी क्षमता से नहीं हो पा रही है तो मुख्यालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी मिलने के बाद जमीनी जांच का क्या होगा?

छत्तीसगढ़ शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
::मंत्रालय::
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

// आदेश //

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 18-09-2026

क्रमांक ESTB/1241/2026-HEALTH SECTION-2: राज्य शासन एतद्द्वारा श्री आशीष कुमार यादव, अभिहित अधिकारी, कार्यालय उप संचालक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, जिला-बेमेतरा को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ उपायुक्त (खाद्य), कार्यालय नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, नवा रायपुर का अतिरिक्त प्रभार एवं श्रीमती नीलम ठाकुर, अभिहित अधिकारी, कार्यालय उप संचालक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, जिला- कोरिया को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ उप संचालक (खाद्य), कार्यालय नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, नवा रायपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
Digitally signed by
VIJAY KUMAR CHOUDHARY
Date: 18-09-2026
(विजय कुमार चौधरी)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञापांक ESTB/1241/2026-HEALTH SECTION-2 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 18-09-2026

प्रतिलिपि -
1. विशेष सहायक, मान. मंत्रीजी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,
2. निज सचिव, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,
3. आयुक्त खाद्य सुरक्षा, कार्यालय नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, नवा रायपुर।

जैसा चल रहा है,चलने दो वाली स्थिति तो नहीं?

इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल शासन की निर्णय प्रक्रिया पर भी है, क्या शासन को जिले में खाद्य सुरक्षा की वास्तविक जमीनी जरूरतों की जानकारी है? क्या यह देखा गया कि जिस अधिकारी को मुख्यालय का अतिरिक्त प्रभार दिया जा रहा है,उसकी मूल पदस्थापना वाले जिले में खाद्य सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति क्या है? क्या यह आकलन किया गया कि जिले में नियमित सैंपलिंग, निरीक्षण और कार्रवाई के लिए पर्याप्त अधिकारी उपलब्ध हैं? या फिर प्रशासनिक व्यवस्था का आसान रास्ता यही बन गया है कि जहां पद खाली है, वहां किसी दूसरे अधिकारी को अतिरिक्त प्रभार दे दो और व्यवस्था चलती रहने दो? अगर यही मॉडल लगातार चलता रहा तो अतिरिक्त प्रभार व्यवस्था अस्थायी समाधान से आगे बढ़कर स्थायी प्रशासनिक संस्कृति बन सकती है।

लाखों की लागत वाली सीसी सड़क से गायब हुआ सीमेंट,17 माह में उखड़ी गिट्टियां

डीएमएफ मद से 20 लाख रुपये के लागत से हुआ था निर्माण,गुणवत्ता पर उठे गंभीर सवाल

-ओंकार पाण्डेय-

सूरजपुर/भैयाथान,19 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)।

विकासखंड भैयाथान अंतर्गत ग्राम पंचायत बांसापारा में जिला खनिज संस्थान न्यास (डीएमएफ) मद से करीब 20 लाख रुपये की लागत से निर्मित सीमेंट कंक्रीट (सीसी) सड़क महज करीब 17 माह में ही बदहाल स्थिति में पहुंच गई है,दुर्गा पंडाल (मंदिर) कुम्हारपारा पहुंच मार्ग पर बनाई गई इस सड़क की ऊपरी सतह से सीमेंट की पकड़ खत्म होती नजर आ रही है और जगह-जगह गिट्टियां उखड़कर सड़क पर बिखरी पड़ी हैं,सड़क की मौजूदा स्थिति को देखकर ग्रामीण निर्माण की गुणवत्ता और कार्य के मूल्यांकन को लेकर सवाल उठा रहे हैं, ग्रामीणों का कहना है कि जिस सड़क के निर्माण पर लाखों रुपये खर्च किए गए,वह लंबे समय तक चलने के बजाय निर्माण पूरा होने के कुछ ही समय बाद खराब होने लगी। अब सड़क पर कई स्थानों पर कंक्रीट की ऊपरी परत उखड़ चुकी है और गिट्टियां बाहर आ गई हैं,इससे राहगीरों और दोपहिया वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

कागजों में करीब 20 लाख का मूल्यांकन, जमीन पर उखड़ी गिट्टियां–उपलब्ध सूचना पट्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में डीएमएफ मद से इस कार्य के लिए 20 लाख रुपये की लागत स्वीकृत की गई थी,निर्माण एजेंसी ग्राम पंचायत बांसापारा को बनाया गया था, कार्य की शुरुआत 4 नवंबर 2024 को हुई और इसे 2 अप्रैल 2025 को पूर्ण दर्ज किया गया। कार्य का कुल मूल्यांकन 19 लाख 99 हजार 535 रुपये किया गया है, निर्माण पूर्ण हुए अब करीब 17 माह यानी लगभग 535 दिन बीत चुके हैं,इतने कम समय में सड़क की सतह का इस तरह उखड़ना निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल खड़े कर रहा है, ग्रामीणों का कहना है कि सड़क का निर्माण यदि निर्धारित मापदंडों के अनुरूप किया गया होता तो इतनी जल्दी उसकी ऊपरी परत खराब होने की स्थिति नहीं बननी चाहिए थी।

पहली : दूसरी बारिश में ही खुलने लगी सड़क की परत?–स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार सड़क निर्माण के बाद से ही इसकी मजबूती को लेकर सवाल उठने लगे थे, उनका आरोप है कि निर्माण के दौरान निर्धारित तकनीकी मापदंडों और सीमेंट के सही अनुपात का ध्यान नहीं रखा गया,जिसके कारण सड़क की ऊपरी परत जल्द ही कमजोर होकर टूटने लगी,हालांकि इन आरोपों की वास्तविकता तकनीकी जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकती है, वर्तमान में सड़क पर जगह-जगह गिट्टियां खुली हुई हैं, इससे यह सवाल भी उठ रहा है कि निर्माण के दौरान सामग्री की गुणवत्ता, मिश्रण और सड़क की मोटाई की निगरानी किस स्तर पर की गई थी।

राहगीरों के लिए बढ़ा दुर्घटना का खतरा–सड़क की ऊपरी सतह उखड़ने के कारण जगह-जगह नुकीली गिट्टियां बाहर निकल आई हैं, ऐसे में दोपहिया वाहन चालकों के फिसलने और दुर्घटना का खतरा बना हुआ है, पैदल चलने वाले लोगों को भी असमतल सड़क के कारण परेशानी हो रही है,ग्रामीणों का कहना है कि सड़क का उद्देश्य लोगों को बेहतर आवागमन सुविधा उपलब्ध कराना था, लेकिन निर्माण के महज कुछ समय बाद ही इसकी हालत खराब होने से अब वही सड़क परेशानी का कारण बन रही है।

तकनीकी जांच और जवाबदेही की मांग–ग्रामीणों ने प्रशासन से सड़क निर्माण की निष्पक्ष तकनीकी जांच कराने की मांग की है,उनका कहना है कि कार्य के मूल्यांकन,निर्माण में इस्तेमाल सामग्री, सीमेंट-गिट्टी के अनुपात, सड़क की मोटाई और निर्माण प्रक्रिया की जांच होनी चाहिए,साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाना चाहिए कि कार्य पूर्ण होने के बाद उसका मूल्यांकन किस आधार पर किया गया और निर्माण के करीब 17 माह बाद सड़क की यह स्थिति क्यों बनी, ग्रामीणों की मांग है कि यदि तकनीकी जांच में निर्माण में किसी तरह की कमी सामने आती है तो संबंधित निर्माण एजेंसी के साथ-साथ निगरानी और गुणवत्ता परीक्षण से जुड़े जिम्मेदारों की जवाबदेही तय की जाए, 20 लाख रुपये की लागत से बनी सड़क का 17 माह में ही इस तरह उखड़ना अब सिर्फ ग्रामीणों की परेशानी नहीं, बल्कि डीएमएफ राशि से कराए जा रहे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और निगरानी व्यवस्था पर भी बड़ा सवाल बन गया है।

रजनीकांत की तरह काम के प्रति समर्पित होना चाहते हैं विजय सेतुपति

डायरेक्टर बालाजी थारानीथरन की बहुप्रतीक्षित तमिल फिल्म बत्था में मुख्य भूमिका निभाने वाले एक्टर विजय सेतुपति ने कहा है कि वह अपने काम के प्रति सुपरस्टार रजनीकांत की तरह ही समर्पित रहना चाहते हैं। शहर के सत्यभामा इंजीनियरिंग कॉलेज में आयोजित फिल्म के ऑडियो लॉन्च इवेंट में शामिल होते हुए एक्टर ने कई बातों के अलावा कहा,सुपरस्टार रजनीकांत ही वो व्यक्ति हैं जिन्हें मैं हमेशा से बहुत पसंद करता रहा हूँ और जिनसे मैं बहुत प्रभावित रहा हूँ। उन्होंने आगे बताया,मैंने हाल ही में जेलर 2 के एक सीन में काम किया था। मैं सेट पर गया था। यह बस एक छोटा सा शॉट था। मुझे और उन्हें (रजनीकांत) किसी बात पर चर्चा करनी थी। डायरेक्टर नेल्सन सुपारी, पान के पत्ते और लौंग लेकर आए और रजनीकांत से कहा, अगर आपको ज़रूरत हो तो कृपया इनका इस्तेमाल करें। रजनीकांत सर के पास जो अनुभव है, उसे देखते हुए उन्हें रिहर्सल करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन उन्होंने लौंग का एक टुकड़ा और थोड़ी सुपारी ली और उन्हें चबाना शुरू कर दिया, साथ ही पान के पत्ते भी मोड़ने लगे। मुझे एहसास हुआ कि वह यह देख रहे थे कि मुझे डायलॉग बोलने में कितना समय लगता है और क्या वह समय पान का पत्ता मोड़ने में लगने वाले समय के साथ मेल खाता है। उन्होंने इसकी पाँच-छह बार रिहर्सल की। विजय सेतुपति ने कहा,अगर कोई एक चीज़ है जिसे मैं पूरे दिल से चाहता हूँ, तो वह यह है कि जब तक मैं जीवित हूँ और एक एक्टर के तौर पर काम कर रहा हूँ,मैं उन्हीं की तरह बनूँ। मैं अपने काम के प्रति उनकी तरह ही समर्पित रहना चाहता हूँ। जो लोग नहीं जानते, उन्हें बता दें कि फिल्म के मेकर्स ने हाल ही में द वर्ल्ड ऑफ़ बत्था नाम से फिल्म का एक झलक वीडियो जारी किया था। झलक वीडियो की शुरुआत बत्था के करीबी लोगों से होती है जो बेसब्री से उसकी वापसी का इंतज़ार कर रहे हैं। यह साफ़ है कि फिल्म अस्सी के दशक की पृष्ठभूमि पर आधारित है। जहाँ बत्था की बेटी कहती है कि वह डरी हुई है और चाहती है कि उसके पिता वापस आ जाएँ, वहीं उसका भाई पूरे आत्मविश्वास के साथ कहता है कि उसका भाई ज़रूर वापस आएगा। एक छोटा बच्चा कहता हुआ दिखाई देता है,सब उससे डरते हैं लेकिन वह किसी चीज़ से नहीं डरता। झलक वीडियो में यह भी दिखाया गया है कि लोगों को किसी बड़े अपराध के होने की आशंका है और पुलिस लोगों से पूछती हुई दिखाई देती है कि क्या उन्हें किसी पर शक है। बत्था की झलक दिखाने वाले वीडियो में बत्था एक ऐसे गुंडे के तौर पर दिखता है जो लोगों को पीटता रहता है। वीडियो से यह भी लगता है कि वह एक अच्छा पति नहीं है। एक सीन में वह अपनी पत्नी के परोसे हुए खाने को थूक देता है। एक और सीन में, उसकी पत्नी (लिजोमोल जोस) उससे पूछती है कि वह कहाँ था और वे उसे ढूँढ रहे थे। वह घमंड भरे लहजे में जवाब देता है, तुम्हें मुझे ढूँढना नहीं चाहिए। मैं खुद ही मिल जाऊँगा। विजय सेतुपति और लिजोमोल जोस की मुख्य भूमिकाओं वाली बत्था को बालाजी थारानीथरन ने डायरेक्ट किया है, जो सुपरहिट फिल्म नडुवुला कोंजम पक्काथा कानोम के लिए जाने जाते हैं। इसे मशहूर डायरेक्टर एटली ने पेश किया है। टेक्निकल पक्ष की बात करें तो, बत्था में संगीत साई अभ्यंकर का है और सिनेमैटोग्राफी सेल्वाकुमार एस.के. ने की है। फिल्म की एडिटिंग आर. कलाईवानन ने की है, जबकि टी. मुथुराज इसके प्रोडक्शन डिज़ाइनर रहे हैं।

गोलमाल 5 में फिर मिलेगा एंटरटेनमेंट का डबल डोज,2027 में धमाका करेंगे रोहित शेट्टी,सामने आई फिल्म की रिलीज डेट

गोलमाल 5 के साथ आपका पसंदीदा गैंग वापस आ रहा है। यह कॉमेडी फ्रैंचाइजी नए साल 2027 में सिनेमाघरों में लौट रही है। रोहित शेट्टी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में अजय देवगन,अरशद वारसी,तुषार कपूर,श्रेयस तलपड़े,शरमन जोशी,अक्षय कुमार और कुणाल खेमू हैं। दर्शकों के लिए गोलमाल फिल्म देखने का मतलब कुछ घंटों के लिए टेंशन से दूर दिल खोलकर हंसना है। हंसी, मस्ती और फैमिली एंटरटेनमेंट से भरपूर इस फिल्म के अब तक 4 भाग आ चुके हैं और अब गोलमाल 5 नए साल में लोगों को फिर से लोगों को हंसाने के लिए तैयार है। रोहित शेट्टी ने गोलमाल 5की रिलीज डेट का ऐलान कर दिया है, जो सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। गोपाल और माधव की नोकझोंक से लेकर लकी के मजेदार नाटक और मस्ती से भरपूर अफरा-तफरी तक, यह फ्रेंचाइजी सालों से बॉलीवुड कॉमेडी का अहम हिस्सा रही है। अब गोलमाल 5 की गैंग फिर से धूम मचाने आने वाली है।

गोलमाल 5 की गैंग का नए साल में होगा धमाका

गोलमाल 5 सिनेमाघरों में 8 जनवरी 2027 को रिलीज होने के लिए तैयार है,जिससे प्रशंसकों को नए साल की शुरुआत करने का एक मजेदार मौका मिलेगा। निर्माताओं ने रिलीज की तारीख की घोषणा इस लाइन के साथ की,हंसी,मजा,खुशी,आनंद और परिवार...बस और कुछ नहीं। 8 जनवरी 2027 अक्षय कुमार गोलमाल 5 की कास्ट में शामिल हो गए हैं और उनकी एंट्री का पता तब चला,जब इस साल की शुरुआत में फिल्म की आधिकारिक घोषणा की गई थी। गोलमाल 5 में अक्षय कुमार,अजय देवगन,अरशद वारसी,तुषार कपूर,श्रेयस तलपड़े, शरमन जोशी और कुणाल खेमू साथ में दर्शकों को हंसाने के लिए तैयार हैं।

गोलमाल 5 में नए-पुराने एक्टर की वापसी

इस फिल्म के साथ रोहित शेट्टी एक बार फिर डायरेक्टर के तौर पर लौटे हैं और अजय देवगन गोपाल के रोल में वापस आए हैं। इस पांचवीं फिल्म में अरशद वारसी, तुषार कपूर, कुणाल खेमू और श्रेयस तलपड़े भी वापसी कर रहे हैं। शरमन जोशी भी इस फ़्रैंचाइजी में लौट रहे हैं। 2006 में रिलीज हुई पहली गोलमाल : फन अनलिमिटेड के बाद यह उनकी वापसी है। वहीं इस बार अक्षय कुमार के रूप में एक नया चेहरा भी फिल्म में शामिल हुआ है।

हंसी-मस्ती से भरपूर होगी गोलमाल 5

गोलमाल फ्रैंचाइजी रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित एक लोकप्रिय भारतीय कॉमेडी फिल्म सीरीज है। इस फ्रैंचाइजी की शुरुआत 2006 में गोलमाल : फन अनलिमिटेड से हुई थी और इसके बाद 2008 में गोलमाल रिटर्न्स, गोलमाल 3 2010 में आई, 2017 में गोलमाल अगेन और अब 207 में गोलमाल 5 रिलीज होने वाली है। पहली तीन फिल्में ढिलिन मेहता ने प्रोड्यूस की थीं, जबकि चौथी फिल्म रोहित शेट्टी और संगीता अहीर ने प्रोड्यूस की थी।

जेनिफर विंगेट की इंडियन वेडिंग की तैयारी शुरू,दोस्तों और परिवार संग जमकर की मस्ती

यूके में शादी के बाद अब जेनिफर विंगेट मुंबई में भारतीय रीति-रिवाजों के साथ अपनी शादी का जश्न मनाने वाली हैं। एक्ट्रेस की शादी की रस्मों में जेनेलिया देशमुख, रितेश देशमुख और आशीष चौधरी भी शामिल हुए। यूके में अपने पति विलियम इश्माइल के साथ क्रिश्चियन शादी के बाद टीवी और ओटीटी स्टार जेनिफर विंगेट अब इंडियन स्टाइल में भी शादी करने जा रही हैं। ऐसा लगता है कि जेनी ने मुंबई में इंडस्ट्री के अपने खास दोस्तों और परिवार के लिए मेहंदी पार्टी रखी थी, क्योंकि एक्ट्रेस ने अपने हनीमून और शक : ट्रस्ट नो वन के प्रमोशन से समय निकालकर यह पार्टी की। ङ्ग और इंस्टाग्राम पर कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिनमें एक्ट्रेस को पार्टी वेन्यू पर अपने पति विलियम इश्माइल के साथ देखा जा सकता है। एक्ट्रेस की खुशी का जश्न मनाने के लिए उनके करीबी दोस्त रितेश देशमुख, जेनेलिया डिसूजा,करण वाही,ऐश्वर्या सखूजा,आशीष चौधरी, मंदिरा बेदी और मुश्ताक शेख जैसे कई लोग शामिल हुए।

जेनिफर विंगेट का इंडियन वेडिंग लुक वायरल

जेनिफर विंगेट ने 16 जुलाई को वेस्ट वेल्स,यूके में विलियम इश्माइल से शादी की। अब गोवा में हुई उनकी मजेदार शादी के अंदर के वीडियो ऑनलाइन सामने आए हैं और देखते ही देखते वायरल हो गए हैं। इन क्लिप्स में जेनिफर विंगेट बहुत खुश नजर आ रही हैं और अपने दोस्तों के साथ जमकर पार्टी कर रही हैं। एक्ट्रेस ने पिंक कलर का डॉट्स वाला लहंगा पहना, जिसे उन्होंने पर्पल ब्लाउज, भारी ज्वेलरी और मेसी बन के साथ पेयर किया। उन्होंने अपने लुक में गजरा भी शामिल किया। वहीं विलियम ने आइस ब्लू कलर का कुर्ता सेट पहना था।

जेनिफर विंगेट की क्रिश्चियन वेडिंग

एक्ट्रेस ने 16 जुलाई 2026 को साउथ वेल्स, यूके के मारगम एबे चर्च में एक प्राइवेट क्रिश्चियन सेरेमनी में सिंगापुर के फाइनेंस प्रोफेशनल विलियम इश्माइल से शादी की। एक्ट्रेस ने अपने सोशल मीडिया पर फेयरी टेल वेडिंग की तस्वीरें और वीडियो शेयर कर फैंस को पति का चेहरा दिखाया था। जेनिफर के उलट,विलियम इश्माइल फिल्म या टेलीविजन इंडस्ट्री से नहीं हैं। वह सिंगापुर में रहने वाले एक फाइनेंस प्रोफेशनल हैं और उन्होंने अपने करियर का ज्यादातर समय ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट में काम करते हुए बिताया है। जेनिफर के साथ उनके रिश्ते के सार्वजनिक होने से पहले उनकी निजी जिंदगी के बारे में बहुत कम जानकारी थी। वह अभी एमएचसी डिजिटल ग्रूप में बिजनेस डेवलपमेंट और ट्रेडिंग के डायरेक्टर के तौर पर काम कर रहे हैं। बताया जाता है कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में कई साल बिताने के बाद वह 2022 में इस ऑर्गनाइजेशन से जुड़े। इससे पहले उन्होंने यूबीएस इन्वेस्टमेंट बैंक में काम किया,जहां वह फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग में माहिर थे।

शादी के बाद जेनिफर विंगेट की पहली सीरीज

एक्ट्रेस नेटफ्लिक्स की अपकमिंग सीरीज शक : ट्रस्ट नो वन में नजर आने वाली हैं। जेनिफर विंगेट का यह शादी के बाद पहला बड़ा प्रोजेक्ट है। यह शो 24 सितंबर 2026 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगा। इस सीरीज से परिणीति चोपड़ा अपना ओटीटी डेब्यू कर रही हैं और इसमें जेनिफर विंगेट, सोनी राजदान,अनूप सोनी, ताहिर राज भसीन, हरलीन सेठी, सुमीत व्यास और ध्रुव चौधरी भी शामिल हैं।

खुद स्टंट करने को शोभिता धूलिपाला ने माना एक चुनौती

एक्ट्रेस शोभिता धूलिपाला ने पा. रंजीत की फिल्म वेत्तुवम में अपने रोल के लिए मल्लखंब की तैयारी के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि हालांकि कुछ सीन की रिहर्सल के लिए स्टंट डबल्स का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन कास्ट ने हर स्टंट खुद करने का फैसला किया और इसे एक चुनौती के तौर पर लिया। फिल्म की एक्शन से भरपूर दुनिया के लिए कास्ट को पारंपरिक फिजिकल और मार्शल आर्ट्स की कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ा। शोभिता ने एक बयान में कहा- ÷इस रोल की तैयारी ने मेरे दिमाग और शरीर को नई तरह की जागरूकता से भर दिया।÷ उन्होंने आगे कहा- ÷कुछ सीन की कोरियोग्राफी के लिए सालों की मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस की ज़रूरत थी, इसलिए रिहर्सल के लिए स्टंट डबल्स होने के बावजूद, हम सभी ने हर स्टंट खुद करने का फैसला किया। हम एक बहुत मज़बूत टीम थे; हमने इसे एक चुनौती के तौर पर लिया।÷ एक्ट्रेस ने कहा कि यह ÷बहुत प्रेरणादायक स्थिति÷ है।

गणपति विसर्जन डांस पर ट्रोल हुई दीपिका सिंह अब दिया जवाब

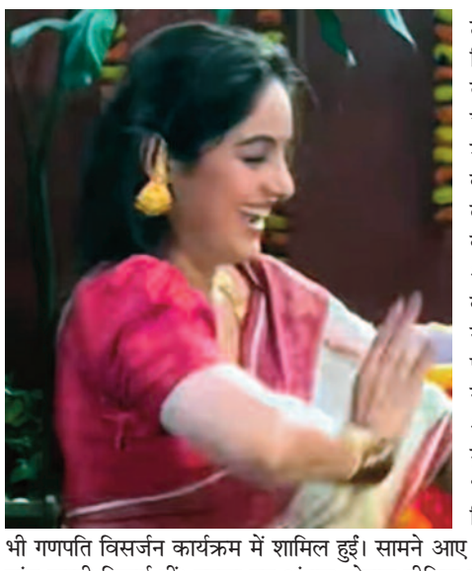

टीवी अभिनेत्री दीपिका सिंह इन दिनों अपने गणपति विसर्जन के दौरान किए गए डांस को लेकर चर्चा में हैं। सोशल मीडिया पर उनका वीडियो वायरल होने के बाद कुछ यूजर्स ने उनके डांस को लेकर आलोचनात्मक टिप्पणियां कीं। ट्रोलिंग के बीच दीपिका ने अपने अंदाज का बचाव करते हुए कहा कि हर कोई कला को नहीं समझ सकता। अभिनेत्री की इस प्रतिक्रिया के बाद यह मामला सोशल मीडिया पर और चर्चा में आ गया। गणपति उत्सव के दौरान मुंबई में अलग-अलग स्थानों पर भक्तों ने धूमधाम से बप्पा को विदाई दी। इसी दौरान दीपिका सिंह भी गणपति विसर्जन कार्यक्रम में शामिल हुईं। सामने आए वीडियो में वह भक्ति गीतों पर डांस करती दिखाई दीं। उनका यह अंदाज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया।

खेल-समाचार

47 साल के गेंदबाज ने रचा इतिहास

सीपीएल क्वालीफायर मैच में तोड़ा सुनील नरेन का महारिकॉर्ड

गुयाना,19 सितम्बर 2026। इमरान ताहिर ने सीपीएल 2026 में इतिहास रच दिया है। वे 146 विकेट लेकर कैरेबियन प्रीमियर लीग के सबसे सफल गेंदबाज बन गए हैं। ताहिर ने सुनील नरेन के 145 विकेटों का रिकॉर्ड तोड़कर इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं।

कैरेबियन प्रीमियर लीग 2026 (सीपीएल 2026) का क्वालीफायर-2 बारबाडोस के केंसिंग्टन ओवल स्टेडियम में खेला गया था। इस मैच में गयाना अमेजन वॉरियर्स के कप्तान इमरान ताहिर ने जमैका किंग्समैन के खिलाफ मैच में सिर्फ एक विकेट लेकर नया इतिहास रच दिया। इमरान ताहिर अब वेस्टइंडीज के स्टार ऑलराउंडर सुनील नारायण का एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़कर सीपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। इस मैच में अंत में गयाना की टीम को हार का सामना करना पड़ा और इसके साथ ही जारी टूर्नामेंट में उनकी टीम का सफर समाप्त हो गया है।

इमरान ताहिर ने तोड़ा सुनील नरेन का बड़ा रिकॉर्ड

इमरान ताहिर ने सुनील नरेन का रिकॉर्ड तोड़कर कैरेबियन प्रीमियर लीग (सीपीएल) के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। ताहिर ने 102 मैचों में शानदार प्रदर्शन करते हुए 146 विकेट झटके हैं, जबकि नरेन 136 मैचों में 145 विकेटों के साथ दूसरे स्थान पर खिसक गए हैं। इसके अलावा ड्वेन ब्रावो (129 विकेट), जेसन होल्डर (121 विकेट) और आंद्रे रसेल (112 विकेट) इस लिस्ट में ताहिर से काफी पीछे हैं। ताहिर ने इसी छ्व्क्क में एक और रिकॉर्ड अपने नाम किया था।

सीपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज
इमरान ताहिर - 146 विकेट (102 मैच)
सुनील नारायण - 145 विकेट (136 मैच)
ड्वेन ब्रावो - 129 विकेट (107 मैच)
जेसन होल्डर - 121 विकेट (124 मैच)
आंद्रे रसेल - 112 विकेट (125 मैच)

सीपीएल2026 में भी सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर हैं ताहिर इमरान ताहिर टी20 फॉर्मेट के बेहद शानदार गेंदबाज हैं और उन्होंने साल 2026 की कैरेबियन प्रीमियर लीग (सीपीएल) में भी सबसे बेहतरीन गेंदबाजी करके इसे साबित कर दिखाया है। इस सीजन में उन्होंने 12 मैचों में कुल 16 विकेट झटके। हालांकि हुनैन शाह और मैथ्यू फोर्ड ने भी 16-16 विकेट लिए हैं, लेकिन ताहिर की इकॉनमी रेट बाकी बॉलर्स से काफी कम है जिसकी वजह से वह फिलहाल सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर हैं।

जमैका किंग्समेन की टीम पहुंची फाइनल में...

इस मैच में जमैका किंग्समेन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। जवाब में गयाना अमेजन वॉरियर्स ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 206 रनों का विशाल स्कोर बनाया, जिसमें शिमरोन हेटमायर ने सिर्फ 45 गेंदों पर नाबाद 102 रनों की तूफानी शतकीय पारी खेली। हालांकि, 207 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी जमैका की टीम ने शानदार खेल दिखाया। कीसी कार्टी (56 रन), माज सदाकत (41 रन) और कप्तान रोवमैन पॉवेल (17 गेंदों में नाबाद 40 रन) की बेहतरीन पारियों की बदौलत जमैका ने 19.4 ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर मैच 5 विकेट से अपने नाम कर लिया और फाइनल में जगह पक्की की।

जापान में एशियाई खेलों का आगाज भारतीय दल ने बिखेरी चमक

नागोया ,19 सितम्बर 2026। जापान के आइची-नागोया में शनिवार, 19 सितंबर को 20वें एशियाई खेलों का भव्य उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। पालोमा मिजुहो स्टेडियम में हुए समारोह में भारत की स्टार निशानेबाज मनु भाकर और कबड्डी खिलाड़ी पवन सहरावत तिरंगा लेकर भारतीय दल के आगे चले। दोनों को उद्घाटन समारोह के लिए भारत का ध्वजवाहक बनाया गया था। समारोह की तस्वीरें और वीडियो भी सामने आए हैं। खिलाड़ियों की परेड के दौरान भारतीय दल ने स्टेडियम में प्रवेश किया तो मनु भाकर और पवन सहरावत सबसे आगे तिरंगा थामे नजर आए। भारत ने इन खेलों के लिए 36 खेलों में 503 खिलाड़ियों का दल उतारा है। उद्घाटन समारोह के साथ एशिया के इस बड़े बहु-खेल आयोजन की औपचारिक शुरुआत हुई। मनु भाकर के लिए ध्वजवाहक बनना उनके करियर का एक और खास सम्मान है। उन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में दो कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा था। वह स्वतंत्र भारत की पहली ऐसी खिलाड़ी बनी थीं, जिन्होंने एक ही ओलंपिक संस्करण में दो पदक जीते। एशियाई खेलों में वह महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल, 25 मीटर पिस्टल और 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम स्पर्धा में हिस्सा लेने वाली हैं।

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी,जशपुर वनमण्डल, जशपुर

नीलाम सूचना

सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि जशपुर वनमण्डल के अन्तर्गत काष्ठागार गम्हरिया (जशपुर) में उपलब्ध निम्नांकित ईमारती एवं जलाऊ काष्ठ का दर्शित तिथि एवं समय में ई-ऑक्शन द्वारा निर्वर्तन किया जावेगा। इच्छुक पंजीकृत व्यापारियों को सलाह दी जाती है कि ई-ऑक्शन में अवश्य भाग लेवें । ई-आक्शन की शर्तें एवं अन्य जानकारी कार्यालयीन दिवस व समय पर वनमण्डल कार्यालय अथवा काष्ठागार गम्हरिया से प्राप्त की जा सकती है ।

प्रजाति	नीलाम में प्रस्तावित अनुमानित मात्रा						मिश्रित जलाऊ चट्टा,
	नया लाट		पुराना लाट		योग		
	लट्ठा घ.मी.	बल्ली+ डेंगरी नग	लट्ठा घ.मी.	बल्ली+ डेंगरी नग	लट्ठा घ.मी.	बल्ली+ डेंगरी नग	
1	2	3	4	5	6	7	8
सागौन	9.499	156	160.892	3389	170.391	3545	पुराना
साल	0.000	0	2258.186	7806	2258.186	7806	27
बीजा, शीशम,खम्हार	0.000	0	26.023	733	26.023	733	नया
अन्य प्रजाति	0.000	0	75.042	7097	75.042	7097	0
चिरान काष्ठ	0.000	0	3.557	279	3.557	279	
योग	9.499	156	2523.700	19304	2533.199	19470	27

उपरोक्त मात्रा में परिवर्तन संभावित है ।

टीप -1. केता को ई-ऑक्सन के पूर्व MSTC E-commerce पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है।
2. क्रेताओं को ई-ऑक्सन के पूर्व कय लॉटों के अपसेट प्राईज मूल्य के 10 प्रतिशत की राशि अपने वॉलेट में रखना अनिवार्य है, सफल बोलीदार को एक सप्ताह के भीतर 15 प्रतिशत EMD की राशि जमा करना अनिवार्य है।
3. लॉट की थप्पी एवं फोटो MSTC E-commerce पोर्टल में अपने आई डी से लॉगईन करके देख सकते है।
4 ई-ऑक्शन में लॉट कय के पश्चात प्रथम केता को 30 सेकण्ड का समय प्राप्त होगा,उसी लॉट में अन्य केताओं द्वारा 30 सेकण्ड पूर्व कय करने पर 20 सेकण्ड का समय प्राप्त होगा।

जी.नं.-262703350/2

वनमण्डलाधिकारी
जशपुर वनमण्डल जशपुर

न्यायालय नजूल अधिकारी अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा,

रा0प्र0क्र0 - ..../20 (1)/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक / आवेदिका श्रीमती शांति यादव आ0/ पति स्व0 सुरेश यादव जाति बरगाह निवासी दर्रीपारा, अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ0ग0 के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि मोहल्ला-दर्रीपारा, शीट नम्बर-10 नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल प्लाट नम्बर 3757, 3758 रकबा 0.13, 0.06 एकड़ भूमि का लीज अवधि दिनांक 31.3.2026 को समाप्त हो गई है। जिस कारण आवेदक / आवेदिका द्वारा लीज अवधि बढ़ाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः उक्त के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा / आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक- 25.09.2026 तक इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा / आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांकः- 11.09.2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी ।

सील

नजूल अधिकारी ,अंबिकापुर

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार अम्बिकापुर - 2, जिला- सरगुजा (छ0ग0)

रा0प्र0क0 /अ-6/2025 26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक अभिषेक अग्रवाल आ. शंकरलाल अग्रवाल, जाति अग्रवाल, निवासी ग्राम श्रीगढ़, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ0ग0 द्वारा ग्राम श्रीगढ़ स्थित भूमि खसरा नंबर 140 / 2 रकबा 0.052 हे0 भूमि पर से पंजीबद्ध दानपत्र दिनांक 17.09.2025 के आधार पर दानकर्ता सुनिता अग्रवाल पत्नी शंकरलाल अग्रवाल, जाति अग्रवाल, निवासी ग्राम श्रीगढ़, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ0ग0 का नाम विलोपित कराकर उपरोक्त दानपत्र के आधार पर अपना नाम दर्ज कराने बावत् आवेदन पत्र छ0ग0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 110 के तहत् प्रस्तुत किया गया है।

उक्त संबंध में किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो पेशी दिनांक 25/09/2026 को न्यायालय में स्वंय अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। समय सीमा के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा ।

आज दिनांक 11/09/ 2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी ।

सील

अतिरिक्त तहसीलदार, अम्बिकापुर-2

C M Y K

SECL खदान के लिए अस्पताल तोड़ने पर भड़के ग्रामीण...जीएम दफ्तर के बाहर प्रदर्शन,पुलिस से झड़प

कोरबा,19 सितम्बर 2026। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में SECL गेवरा खदान के नए प्रोजेक्ट के लिए सरकारी अस्पताल को तोड़ दिया गया। इसके विरोध में ग्रामीण धरने पर बैठ गए हैं। दरअसल, हरदीबाजार में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन पर उस वक्त बुलडोजर चलाया गया, जब कई लोग इलाज कराने भी पहुंचे हुए थे। इसके अलावा छात्रावास,आंगनबाड़ी और पटवारी ऑफिस भी ढहा दिया गया है। शनिवार को कटघोरा से बीजेपी विधायक प्रेमचंद पटेल के नेतृत्व में बड़ी संख्या में ग्रामीण दीपका स्थित SECL के मुख्य महाप्रबंधक दफ्तर पहुंचे और मेन गेट पर तालाबंदी कर दी। इस दौरान मौके पर पुलिस बल तैनात है। ग्रामीणों ने 100 प्रतिशत मुआवजा, नौकरी, बसाहट और वैकल्पिक अस्पताल की मांग की है। प्रदर्शन में हरदीबाजार,सराई सिंगार, रेंकी और आसपास के गांवों के सैकड़ों लोग शामिल हैं। SECL प्रबंधन के मुताबिक, जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई के तहत सरकारी भवनों को तोड़ा गया है। कर्मचारियों का आरोप है कि स्वास्थ्य विभाग,पटवारी कार्यालय और आंगनबाड़ी से दस्तावेज और जरूरी सामान बाहर निकालने का पर्याप्त मौका नहीं दिया गया। कर्मचारियों के मुताबिक,दवाइयां,दस्तावेज और अन्य सामग्री भवनों के मलबे में दब गई। कार्रवाई के दौरान कई मरीज रोज की तरह स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे थे। अस्पताल भवन को तोड़े जाने की कार्रवाई देखकर उन्हें बिना इलाज कराए वापस लौटना पड़ा। मरीजों और उनके परिजनों ने बताया कि उन्हें इस कार्रवाई की जानकारी पहले से नहीं थी।

बारिश में खराब सड़कों को लेकर डिप्टी सीएम साव ने जताई नाराजगी, 15 अक्टूबर तक सुधारने का दिया अल्टीमेटम

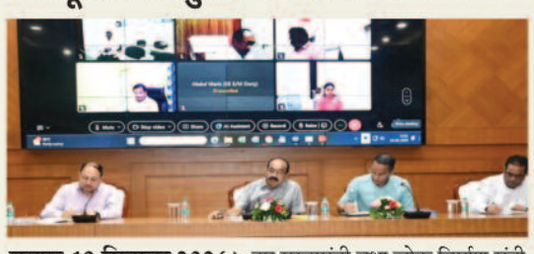

रायपुर,19 सितम्बर 2026। उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने आज सभी परिक्षेत्रों के मुख्य अभियंताओं, मंडलों के अधीक्षण अभियंताओं और संभागों के कार्यपालन अभियंताओं की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने प्रदेशभर में सड़कों और पुलों की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने बारिश में सड़कों की खराब स्थिति पर गहरी नाराजगी जताते हुए राष्ट्रीय राजमार्गों सहित सभी क्षतिग्रस्त सड़कों और पुलों की मरम्मत 15 अक्टूबर तक करने के निर्देश दिए। इतना ही नहीं प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त ऐसे सभी नए कार्यों जिनकी निविदा की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है,उनके निर्माण 15 अक्टूबर से युद्धस्तर पर प्रारंभ करने को कहा। लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल और प्रमुख अभियंता वी.के.भतपहरी भी बैठक में मौजूद थे। सभी संभागों के कार्यपालन अभियंता वीडियो कॉन्फ्रेंस से बैठक में जुड़े। उप मुख्यमंत्री साव ने नवा रायपुर में पीडब्लूडी मुख्यालय 'निर्माण भवन' में आयोजित बैठक में सड़कों की मरम्मत की पुख्ता कार्ययोजना तैयार कर बरसात के बाद तत्काल क्षतिग्रस्त सड़कों को सुधारने के निर्देश दिए। सभी संभागों को मांग के अनुसार मरम्मत और संधारण के लिए पर्याप्त राशि दी जाएगी। उन्होंने इसके लिए तत्काल निविदा कर एजेंसी तय करने के निर्देश दिए। साथ ही सभी कार्यपालन अभियंताओं को अगले दो-तीन दिनों में अपने कार्यक्षेत्र का भ्रमण कर सड़कों और पुलों की स्थिति जांचने को कहा। इतना ही नहीं उन्होंने सड़कों,पुलों और डिवाइडर्स की मरम्मत के साथ ही उनकी साफ-सफाई एवं रंगाई-पुताई भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए और सभी कार्यपालन अभियंताओं को सप्ताह में दो-तीन दिन फील्ड में रहने को कहा।

उधारी का 30-लाख नहीं देने पर टीचर ने की हत्या...जंगल ले जाकर हथौड़े से दोस्त का सिर फोड़ा,ट्रेडिंग के लिए दिए थे पैसे

रायपुर,19 सितम्बर 2026। रायपुर में एक टीचर ने ट्रेडिंग करने वाले अपने दोस्त की हत्या कर दी। चंद्रप्रकाश वर्मा ने अपने साथी शिवकुमार चंद्राकर को 30 लाख उधार दिए थे। इसके बदले वह ब्याज लेता था। पिछले तीन महीने से उसे ब्याज नहीं मिला था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद चल रहा था।पेशे से दोनों टीचर थे और एक ही स्कूल में पढ़ाते थे। 17 सितंबर को आरोपी प्लानिंग के तहत उसे अपने साथ स्कूटी पर बैठाकर सुनसान जंगल ले गया। वहां उसने हथौड़े से शिवकुमार का सिर फोड़ा और धारदार हथियार से चेहरे पर वार कर मार डाला। मामला आरंग थाना क्षेत्र के महानदी तट के बनचरौदा के पास का है।

मुख्यमंत्री ने चौथे बीएमसी छत्तीसगढ़ कैंसर कॉन्क्लेव-2026 का किया शुभारंभ

कैंसर के खिलाफ लड़ाई में मरीज को यह भरोसा दिलाना जरूरी कि वह अकेला नहीं : मुख्यमंत्री साय

रायपुर,19 सितम्बर 2026। कैंसर के विरुद्ध लड़ाई केवल बीमारी के उपचार तक सीमित नहीं है। मरीज को आधुनिक और प्रभावी उपचार उपलब्ध कराने के साथ उसका मनोबल बनाए रखना तथा उसे यह विश्वास दिलाना भी उतना ही आवश्यक है कि इस कठिन लड़ाई में वह अकेला नहीं है। चिकित्सकों का संवेदनशील व्यवहार और परिवार एवं समाज का भावनात्मक सहयोग मरीज के भीतर बीमारी से लड़ने का हौसला बढ़ाता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज नवा रायपुर स्थित मेफेयर में बालको मेडिकल सेंटर द्वारा आयोजित चौथे बीएमसी छत्तीसगढ़ कैंसर कॉन्क्लेव-2026 के शुभारंभ अवसर पर संबोधित करते हुए यह बात कही। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि कैंसर आज पूरी दुनिया के सामने गंभीर स्वास्थ्य चुनौतियों में से एक है। कैंसर का नाम सुनते ही मरीज के साथ पूरा परिवार चिंता और अनिश्चितता से घिर जाता है। बीमारी का प्रभाव केवल मरीज के शरीर तक सीमित नहीं रहता,बल्कि उसकी मानसिक, पारिवारिक और आर्थिक परिस्थितियों पर भी पड़ता है। इसलिए कैंसर के उपचार में समग्र दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि चिकित्सक जब आत्मीयता और संवेदनशीलता के साथ मरीज से जुड़ते हैं तो वे केवल बीमारी का उपचार नहीं करते, बल्कि मरीज और उसके परिवार के लिए विश्वास और हौसले का आधार भी बनते हैं। चिकित्सा विज्ञान में हो रही प्रगति के साथ मानवीय संवेदना का यह पक्ष कैंसर के विरुद्ध लड़ाई को और मजबूत बनाता है।

प्रदेश में लगातार मजबूत हो रही स्वास्थ्य अधोसंरचना : मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के समय प्रदेश में केवल एक मेडिकल कॉलेज था। आज शासकीय और निजी मेडिकल कॉलेजों को मिलाकर इनकी संख्या 15 हो गई है। इसके साथ ही पांच नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन चिकित्सा संस्थानों में कैंसर सहित अन्य गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए आवश्यक विशेषज्ञता, आधुनिक उपकरण और अधोसंरचना विकसित करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सरकार का प्रयास है कि प्रदेश के लोगों को गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए दूर न जाना पड़े और उन्हें अपने राज्य में ही गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य सरकार बस्तर जैसे भौगोलिक रूप से चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए विशेष प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान के अंतर्गत लगभग 34 लाख लोगों की स्वास्थ्य स्क्रीनिंग की गई है। इनमें करीब 40 हजार लोगों में विभिन्न बीमारियों की पहचान कर उन्हें उपचार से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि व्यापक स्क्रीनिंग का उद्देश्य बीमारी की शुरुआती अवस्था में ही पहचान करना और मरीज को समय पर उपचार उपलब्ध कराना है। सरगुजा सहित प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी कैंसर सहित गंभीर बीमारियों की पहचान और उपचार के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है।

समय पर पहचान से बढ़ती हैं प्रभावी उपचार की संभावनाएं...

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि कैंसर से लड़ाई में सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक बीमारी की समय पर पहचान है। शुरुआती अवस्था में कैंसर की पहचान होने पर प्रभावी उपचार की संभावनाएं काफी बढ़ जाती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कैंसर सहित गंभीर बीमारियों की समय पर स्क्रीनिंग और रोकथाम को प्राथमिकता दी है। मुख्यमंत्री साय ने कॉन्क्लेव में उपस्थित विशेषज्ञों से आग्रह किया कि वे ऐसी आधुनिक तकनीकों,अनुसंधानों और प्रभावी उपायों पर विचार करें,जिनसे कैंसर की जल्द पहचान हो सके और उपचार को अधिक सस्ता,सुलभ तथा आम लोगों की पहुंच में लाया जा सके। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के कॉन्क्लेव चिकित्सा जगत के अनुभव,शोध और नवाचार को साझा करने का महत्वपूर्ण मंच हैं।

आर्थिक कठिनाई उपचार में न बने बाधा

मुख्यमंत्री ने कहा...कि गंभीर बीमारी के समय उपचार के खर्च की चिंता परिवार की परेशानी को और बढ़ा देती है। सरकार का प्रयास है कि आर्थिक कठिनाई किसी जरूरतमंद व्यक्ति के उपचार में बाधा न बने। आयुष्मान भारत योजना ने गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच आसान की है। पात्र परिवारों को योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक उपचार की सुविधा मिल रही है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के माध्यम से जरूरतमंद मरीजों को 25 लाख रुपए तक की उपचार सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। इन योजनाओं का उद्देश्य यही है कि बीमारी के कठिन समय में परिवार को आर्थिक चिंता के बजाय मरीज के स्वास्थ्य और उपचार पर ध्यान देने का संबल मिले।

झीरम केस...फैसले के खिलाफ कांग्रेस दिल्ली में उठाएगी मुद्दा

हाईकोर्ट जाएगा सर्व आदिवासी समाज,केस लड़ने हर घर से 20 चंदा लेंगे...

रायपुर,19 सितम्बर 2026। झीरम नक्सली हमला मामले में एनआईए कोर्ट के फैसले के खिलाफ कांग्रेस दिल्ली से आवाज उठाने की तैयारी में है। शनिवार को रायपुर में कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल राहुल गांधी से मुलाकात करेगा। दिल्ली में झीरम के फैसले पर पीसी की जाएगी। सीनियर नेताओं से चर्चा कर न्यायिक लड़ाई लड़ी जाएगी। इधर,सर्व आदिवासी समाज ने मामले को हाईकोर्ट ले जाने का निर्णय लिया है। कोया भवन में बस्तर संभाग के 6 जिलों दंतेवाड़ा,बस्तर,सुकमा, नारायणपुर,कोंडागांव और बीजापुर के समाज के पदाधिकारियों की बैठक हुई। इसमें फैसले पर चर्चा के साथ मामले में सजा पाए दोषियों के खिलाफ आगे कानूनी लड़ाई जारी रखने की रणनीति तय की गई। आदिवासी समाज के हर परिवार से 20-20 रुपए चंदा लिया जाएगा। इससे जुटने वाली राशि का इस्तेमाल हाईकोर्ट में मामले की पैरवी और उससे जुड़ी कानूनी प्रक्रिया में किया जाएगा। सर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष प्रकाश ठाकुर ने कहा कि, बैठक में 6 जिलों से समाज के प्रतिनिधि शामिल हुए। सभी ने झीरम मामले में एनआईए कोर्ट के फैसले पर चर्चा की। बैठक में तय किया गया कि जिन 10 दोषियों को सजा सुनाई गई है,उस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी जाएगी। समाज की ओर से कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक दस्तावेज और अन्य पहलुओं पर भी काम किया जाएगा। प्रकाश ठाकुर ने कहा कि इस कानूनी लड़ाई के लिए समाज के स्तर पर आर्थिक सहयोग जुटाया जाएगा।

साजिश और आरोपियों की भूमिका की जांच की मांग

समाज ने बैठक में झीरम घाटी कांड की पूरी साजिश और इसमें शामिल लोगों की भूमिका की दोबारा जांच की मांग भी उठाई। पदाधिकारियों का कहना है कि मामले में जिन लोगों की भूमिका संदिग्ध रही है,उनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इसके साथ ही सरेंडर कर चुके नक्सलियों की भूमिका की भी दोबारा जांच किए जाने की मांग की गई। रायपुर में शनिवार को इसी मामले को लेकर कांग्रेस ने राजीव भवन में अहम बैठक की। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि झीरम मामले में कांग्रेस जल्द ही पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व से समय लेकर मुलाकात करेगी।

बांग्लादेशी बताकर पकड़े गए 23 में से 18 भारतीय निकले

रायपुर डिटेंशन सेंटर से 15 दिन बाद रिहा

बिलासपुर,19 सितम्बर 2026। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के सिरगिट्टी इलाके से बांग्लादेशी नागरिक होने के संदेह में पकड़े गए 23 लोगों में से 18 भारतीय नागरिक निकले हैं। मुर्शिदाबाद और संबंधित थाना क्षेत्रों से दस्तावेज और पहचान का सत्यापन होने के बाद 15 दिन में इन्हें रायपुर के होल्डिंग/डिटेंशन सेंटर से रिहा कर दिया गया। अब बचे 5 लोगों के दस्तावेजों की जांच चल रही है।

पुलिस ने इनके दूसरे दस्तावेज भी मंगाए हैं। कुछ दस्तावेजों में कमी मिली है, जबकि कुछ लोगों के नाम एसआईआर से हटाए जाने की जानकारी भी सामने आई है। पुलिस इन दस्तावेजों की जांच के बाद आगे की कार्रवाई करेगी। दरअसल, स्पेशल टास्क फोर्स गठित कर सिरगिट्टी इलाके में अभियान चलाकर 23 लोगों को संदिग्ध मानते हुए पकड़ा गया था। पुलिस ने बताया था कि,जिले में करीब 2 महीने तक चले अभियान में 1162 लोगों की जांच की गई थी। जिसके बाद इन 23 लोगों के दस्तावेज और पहचान संदिग्ध पाए गए। इसके बाद पुलिस टीम मुर्शिदाबाद,जंगीपुर और आसपास के संबंधित थाना क्षेत्रों तक पहुंची।

आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत,3 घायल

जांजगीर-चांपा,19 सितम्बर 2026। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में शनिवार को बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से तीन लोगों की मौत हो गई। वहीं तीन लोग घायल हुए हैं। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और सभी को अस्पताल पहुंचाया। पूरा मामला बलौदा थाना क्षेत्र के महुदा का है। जानकारी के मुताबिक, शनिवार शाम को अचानक मौसम बदला और तेज बारिश हुई। बाड़ी में काम करने के दौरान बारिश से बचने लोग एक झोपड़ी में रुके थे, जहां आकाशीय बिजली गिरने से तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं तीन लोग घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है।

इनकी हुई मौत : नरेश खैरवार पिता रामू खैरवार उम्र 24 वर्ष पता महुदा थाना बलौदा, रामभरोश पटेल पिता कंश राम पटेल उम्र 32 वर्ष, तुलसी राम पटेल पिता बेदराम पटेल उम्र 51 वर्ष।

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव में छत्तीसगढ़ का डंका...

स्वतंत्र प्रत्याशी पीयूष जायसवाल ने 674 वोटों से दर्ज की ऐतिहासिक जीत

गरियाबंद,19 सितम्बर 2026। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित शहीद भगत सिंह संध्या कॉलेज के छात्रसंघ चुनाव 2026 में स्वतंत्र प्रत्याशी छत्तीसगढ़ के पीयूष जायसवाल ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। बेमेतरा के रहने वाले और देश के सबसे कम उम्र के मशहूर छात्र वैज्ञानिक व शोधकर्ता पीयूष जायसवाल ने किसी भी बड़े राजनैतिक दल का दामन थामे बिना, पूरी तरह स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़कर जॉइंट सेक्रेटरी (संयुक्त सचिव) पद पर एकतरफा चुनाव जीता है। उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वियों को रिकॉर्डतोड़ 674 वोटों से हराकर विजय का परचम लहराया। दिल्ली विश्वविद्यालय के इतिहास में यह पहली बार है जब छत्तीसगढ़ के किसी छात्र ने बिना किसी पार्टी बैनर के सिर्फ अपने दम पर अपनी प्रेरक भाषण शैली और दमदार नेतृत्व के भरोसे इतनी बड़ी जीत दर्ज की हो।

देवभोग गरियाबंद से शुरू हुआ था दुनिया को चौंकाने वाला सफर : पीयूष जायसवाल (सुपुत्रः प्यारे लाल जायसवाल, प्राचार्य - डीएवी बेमेतरा) की यह अद्भुत प्रतिभा नई नहीं है, बल्कि इसकी नींव छत्तीसगढ़ में ही पड़ चुकी थी। पीयूष जब छत्तीसगढ़ के डीएवी देवभोग गरियाबंद में कक्षा 4थी से 7वीं तक की पढ़ाई कर रहे थे, तभी मात्र 12 वर्ष की कम में (कक्षा 7वीं के दौरान) उन्होंने एक नया कीर्तिमान रच दिया था। वे इतनी छोटी सी उम्र में ही लेखक, कवि, वैज्ञानिक और शोधकर्ता बनकर पूरी दुनिया को चौंका चुके थे। उन्होंने ब्रह्मांड के रहस्यों पर अपनी प्रसिद्ध पुस्तक और गति के नियमों पर महत्वपूर्ण शोध पत्र लिखकर बचपन में ही देशभर में नाम रौशन कर दिया था।

21 सितंबर से छत्तीसगढ़ में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल

23 सितंबर से इमरजेंसी सेवाएं बंद करने की चेतावनी,17 सूत्रीय मांगें...

रायपुर,19 सितम्बर 2026। छत्तीसगढ़ के सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में जूनियर डॉक्टर एक बार फिर आंदोलन की तैयारी में हैं। स्टाइपेंड, वेतन-मानदेय में संशोधन समेत 17 सूत्रीय मांगों को लेकर जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन ने 21 सितंबर से ओपीडी के बहिष्कार का ऐलान किया है। मांगों का निराकरण नहीं होने पर 23 सितंबर से इमरजेंसी सेवाओं का भी बहिष्कार करने की चेतावनी दी गई है।

आंदोलन में एमबीबीएस इंटर्न, पीजी रेजिडेंट, सीनियर रेजिडेंट और बॉन्डेड जूनियर रेजिडेंट डॉक्टरों के शामिल होने की बात कही गई है। डॉक्टरों का कहना है कि, मांगों को लेकर पहले भी सरकार को ज्ञापन और पत्र दिए गए थे, लेकिन अपेक्षित कार्रवाई नहीं होने के कारण दोबारा आंदोलन का फैसला लिया गया है। डॉक्टरों के मुताबिक, 19 अगस्त को स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के साथ एमबीबीएस इंटर्न के स्टाइपेंड को लेकर बैठक हुई थी। बैठक के बाद डॉक्टरों ने सरकार से मिले आश्वासन के आधार पर अपना आंदोलन स्थगित कर दिया था। स्वास्थ्य मंत्री की ओर से भी इस संबंध में सोशल मीडिया पर संदेश जारी किया गया था और 1 सितंबर से बढ़ी हुई राशि दिए जाने की बात सामने आई थी। हालांकि, डॉक्टरों का कहना है कि अब तक इस संबंध में कोई ठोस सरकारी आदेश जारी नहीं हुआ है।

आश्वासन के बाद भी आदेश नहीं होने से नाराजगी : डॉक्टरों का कहना है कि सरकार से आश्वासन मिलने के बाद उन्होंने आंदोलन स्थगित किया था, लेकिन मांग पर अब तक अमल नहीं हुआ। इससे प्रदेशभर के चिकित्सकों में नाराजगी है। उनका कहना है कि इससे पहले भी कई दिनों तक आंदोलन करने के बाद उन्हें आश्वासन मिला था, लेकिन मांगों का स्थायी समाधान नहीं हुआ।

डॉक्टरों की प्रमुख मांगें : जूनियर डॉक्टरों की 17 सूत्रीय मांगों में एमबीबीएस इंटर्न के स्टाइपेंड में बढ़ोतरी,पीजी रेजिडेंट, बॉन्डेड जूनियर रेजिडेंट और सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों के वेतन और मानदेय में संशोधन प्रमुख हैं। इसके अलावा डीएम और एमसीएच सुपर-स्पेशलिटी रेजिडेंट के स्टाइपेंड में संशोधन, डॉक्टरों से जुड़ी वेतन विसंगतियों, बॉन्ड से जुड़े मुद्दों का समाधान और चिकित्सा सेवाओं से जुड़े लंबित मामलों के निराकरण की मांग भी शामिल है।

21 सितंबर से ओपीडी, 23 से इमरजेंसी बंद करने की चेतावनी

डॉक्टरों ने चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान किया है। इसके तहत 21 सितंबर से ओपीडी सेवाओं का बहिष्कार किया जाएगा। यदि इसके बाद भी मांगों पर कोई निर्णय नहीं होता है तो 23 सितंबर से इमरजेंसी सेवाओं का भी बहिष्कार करने की चेतावनी दी गई है।

शराब तस्करी में पकड़ा गया सहायक शिक्षक निलंबित

रायपुर में 160 पाव शराब के साथ 7 आरोपी गिरफ्तार...

रायपुर,19 सितम्बर 2026। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में शराब तस्करी के मामले में पकड़े गए सहायक शिक्षक को जिला शिक्षा अधिकारी ने निलंबित कर दिया है। शिक्षक तिरीत राम बांधे शासकीय प्राथमिक शाला अमोदी में पदस्थ हैं और वर्तमान में संकुल समन्वयक प्रभारी की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। पुलिस ने उन्हें शराब की अवैध बिक्री के लिए ले जाते हुए 6 अन्य आरोपियों के साथ पकड़ा था। मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला शिक्षा अधिकारी ने शिक्षक के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की है।

कार में भरकर ले जा रहे थे 160 पाव शराब

मामला 14 सितंबर का है। ग्रामीण एसपी के निर्देश पर आरंग थाना पुलिस की टीम इलाके में गश्त कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि सफेद रंग की आर्टिका कार में ग्राम गुल्लू की शराब दुकान से बड़ी मात्रा में शराब भरकर रानीसागर की ओर ले जाई जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने रानीसागर के हनुमान मंदिर के पास घेराबंदी की। कुछ देर बाद संदिग्ध कार वहां पहुंची, जिसे पुलिस ने रोककर तलाशी ली। कार में चालक समेत 6 लोग सवार थे। तलाशी में कार से 160 पाव देशी मसाला शराब मिली। पुलिस के मुताबिक शराब की कीमत करीब 16 हजार रुपए है। पूछताछ में आरोपियों ने शराब को अवैध बिक्री के लिए ले जाने की बात स्वीकार की।

शराब दुकान के सुपरवाइजर और सेल्समैन भी पकड़े गए

पुलिस ने शराब के साथ परिवहन में इस्तेमाल की जा रही आर्टिका कार भी जब्त की है। इसकी कीमत करीब 8 लाख रुपए बताई गई है। शराब और वाहन समेत जब्त सामान की कुल कीमत करीब 8.16 लाख रुपए है। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

प्रकाशक,मुद्रक,स्वामी अविनाश कुमार सिंह के द्वारा सांई ऑफ्सेट प्रिंटर्स,नमनाकला,संत हरकेवल विद्यापीठ के पास,अम्बिकापुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-अविनाश कुमार सिंह* (पी.आर.बी.कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिए जिम्मेदार)
RNI Reg.No.CHHHIN/2004/15050,डॉक रजिस्टर्ड क्र.:-13/सरगुजा/डीएन/2026-2028-मो. 94062-23001,98265-32611,Email:ghatatighatana11@ gmail.com,Website:www.ghatatighatana.com, (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र अम्बिकापुर न्यायालय मान्य होगा)